



महाकुंभ : दो करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

PRAYAGRAJ @ PTI :

बुधवार को महाकुंभ के पांचवें स्नान पूर्व माघी पूर्णिमा पर शाम 6 बजे तक दो करोड़ लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने इस दौरान, स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई। सुबह से ही महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों समेत श्रद्धालुओं का गंगा और संगम घाट की ओर आगमन जारी रहा। यह जानकारी दी गई है कि काटजू रोड पर मस्जिद के बाहर नमाजियों ने भी श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 13 जनवरी से अब तक 48 करोड़ से अधिक लोग यहां स्नान कर चुके हैं। सभी कल्पवासियों से यथायात नियमों का पालन करने और केवल अधिकृत पार्किंग का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

स्नान करने वालों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा, काटजू रोड पर नमाजियों ने भी श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल

13 जनवरी से अब तक 48 करोड़ से अधिक लोग कर चुके हैं स्नान, महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा मेला

सुबह 4 बजे से निगरानी कर रहे थे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह चार बजे से ही लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में बने वार रूम से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। उनके साथ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर माघी पूर्णिमा

की बधाई देते हुए कहा, महाकुंभ में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान के लिए पधार सभी पुज्य साधु सत्तों, धमाचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। मां गंगा, यमुना और सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना है।



पूरा हुआ 10 लाख कल्पवासियों का संकल्प

महाकुंभ मेले में कल्पवास कर रहे करीब 10 लाख कल्पवासियों का संकल्प माघी पूर्णिमा स्नान के साथ आज पूरा हो गया और वे अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करना शुरू करेंगे। त्रिवेणी संगम आरती सेवा समिति के संस्थापक और तीर्थ पुरोहित राजेंद्र मिश्रा ने

बताया, पिछली पूर्णिमा पर कल्पवास का संकल्प लेने वाले कल्पवासियों का संकल्प आज पूरा हुआ। उन्होंने एक महीने तक सभी यम, नियम और संयम, आदर्श सात्विक जीवन का अक्षरशः पालन करने, भूमि पर शयन करने, तीन बार स्नान करने, स्वयं भोजन बनाकर

एक समय भोजन करने, यथोचित दान करने और गुरु की वाणी का श्रवण करने का संकल्प लिया था। उन्होंने बताया, आज वे मां गंगा का पूजन, दीपदान करके उस संकल्प से मुक्त होंगे और दिशाशूल को देखते हुए अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे।

SHARE

संसेक्स : 76,171.08

निफ्टी : 23,045.25

SARAFU

सोना : 8,115

चांदी : 107.00

(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

नहीं रहे राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास

LUCKNOW : बुधवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास का लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्काघात के बाद एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बताया, राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास जी ने बुधवार को अंतिम सांस ली। उन्हें तीन फरवरी को मस्तिष्काघात के बाद गंभीर हालत में हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया था।

भारत-फ्रांस के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को विकसित करने का आह्वान

मोदी और मैक्रों ने की वार्ता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति

NEW DELHI @ PTI :

बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहलों में अपनी सहभागिता को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक बातचीत के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया कि वैश्विक एआई क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी परिणाम प्रदान करे।

व्यापक बातचीत के बाद ठोस कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को किया रेखांकित

सार्वजनिक हित में वैश्विक एआई क्षेत्र के कार्य करने के अच्छे परिणाम पर दिया जोर

मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस के समर्थन को दोहराया



मोदी ने मैक्रों को भारत आने का दिया निमंत्रण

एक बयान में कहा गया कि हाल में संपन्न एआई एक्शन समिट और 2026 में आगामी भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की पुष्ठभूमि में साझेदारी का यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार की भी वकालत की। राष्ट्रपति मैक्रों ने मारसेई के निकट तटीय शहर कैसिस में प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया।

मोदी ने मैक्रों को भारत आने का दिया निमंत्रण

एक बयान में कहा गया कि हाल में संपन्न एआई एक्शन समिट और 2026 में आगामी भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की पुष्ठभूमि में साझेदारी का यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार की भी वकालत की। राष्ट्रपति मैक्रों ने मारसेई के निकट तटीय शहर कैसिस में प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया।



बजट सत्र के लिए 5 मंत्रियों को सौंपा गया

सीएम के प्रभार वाले विभागों का दायित्व

RANCHI : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह 27 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 25 और 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 28 फरवरी को हिंद सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 3 मार्च को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभागों के सचिवों का जवाब देने के लिए पांच मंत्रियों को दायित्व सौंपा गया है। मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी चमरा लिंडा को सौंपी गई है। रामदास सोरेन को विधि विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, आईटी विभाग का दायित्व दिया गया है। योगेंद्र प्रसाद को गृह, करा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुदित्य कुमार को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का दायित्व मिला है। दीपक विरूपा को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक व संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने एवं अन्य विधायी कार्य के जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट ने इस बाबत में आदेश जारी कर दिया है।

एक साथ महिलाओं के खाते में जाएगी योजना की दो महीने की राशि



PHOTON NEWS RANCHI :

मईयां सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रही हैं। जनवरी में दिसंबर महीने की किस्त मिली थी। फरवरी में एक साथ जनवरी और फरवरी महीने की किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। बता दें कि जनवरी माह की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, पर खातों में 2500 रुपये नहीं आए हैं। अब फरवरी माह की डेडलाइन समाप्त होने को है। नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है।

मईयां सम्मान

हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं ₹2500

समय पर पैसा नहीं मिलने को लेकर भाजपा ने दी है आंदोलन की चेतावनी

जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुका को पैसा जरूर मिलेगा। कांग्रेस और झामुमो का दावा है कि फरवरी में 2 महीने की राशि लाभुकों के खाते में जाएगी।

31 मार्च तक बढ़ी आधार लिंक की समय सीमा

मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने आधार लिंक की समय सीमा को 1000 दिए गए थे। मार्च 2025 कर दिया है। इससे योजना की लाभुक महिलाओं को राहत मिलेगी और वे अपने खातों में राशि प्राप्त कर सकेंगी। 27 दिसंबर को सभी जिलों को 5225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई। 14 अक्टूबर 2024 को जारी संकल्प के अनुसार, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 5900 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया था। बता दें कि यह व्यवस्था अगस्त 2024 से शुरू हुई थी। नवंबर माह तक लाभुकों को 1000 दिए गए थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा सरकार बनने पर गोपी-दीदी योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 2100 देने की घोषणा के जवाब में तत्कालीन सरकार ने 2500 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। कैबिनेट से भी प्रस्ताव को पारित करा लिया गया था। सरकार बनने पर वादे को पूरा करते हुए दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि को 6 जनवरी 2025 को जारी किया था।

उपलब्धि भारत में इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए बना टीका

खतरनाक टाइफाइड बुखार से मुक्ति दिलाएगी मिश्रित वैक्सीन

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

टाइफाइड एक प्रकार के अत्यंत खतरनाक बुखार की स्थिति है। विशेषज्ञ डॉक्टर के अनुसार, इस बुखार के लक्षण अक्सर साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी-ए बैक्टीरिया से संक्रमित होने के एक या दो सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं। उपचार के साथ टाइफाइड बुखार के लक्षण 3-5 दिनों के भीतर कम होने लगते हैं। बच्चों में टाइफाइड बुखार अक्सर कुछ हफ्तों के दौरान खराब हो जाता है। संभावित रूप से घातक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। बच्चों में टाइफाइड के लक्षण वयस्कों के समान ही होते हैं। शरीर के तापमान में तेज वृद्धि, दर्द, भूख में कमी और पावन में गड़बड़ी इस बुखार के प्रमुख लक्षण होते हैं। डॉक्टर के अनुसार, टाइफाइड आंत्र छिद्र जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि जीन के बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं और पेट की परत को संक्रमित कर देते हैं। इससे पेट में सूजन आ जाती है। इस स्थिति में संक्रमण रक्त में फैल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य अंगों में फैलने से पहले सेप्सिस होता है।

सामान्य रूप से इस रोग के इलाज में विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक का होता है प्रयोग राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है वैक्सीन



वर्तमान में देश में हर साल एक करोड़ से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने

जल्द शुरू होगा टीका का परीक्षण

वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक टाइफाइड रोगियों के मामले में भारत शीर्ष पर है। भारत में साल्मोनेला पैराटाइफी ए दोनों ही स्ट्रेन के मामले हर साल बढ़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर ने यह भी बताया कि आगामी दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस टीका पर परीक्षण शुरू होंगे। आईसीएमआर ने दावा किया है कि इस टीके के व्यापक उपयोग से भारत सहित अन्य देशों में इस टीका पर घटनाओं में कमी आ सकती है।

उपचार के साथ तीन से पांच दिनों के भीतर कम होने लगते हैं लक्षण, उचित तरीके से इलाज नहीं होने पर शरीर में पैदा होती हैं कई जटिलताएं

बैक्टीरिया के दोनों प्रकार के स्ट्रेन को समझ करने के लिए डेवलप हुई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया

आईसीएमआर ने टीका उत्पादन और आगे के परीक्षण शुरू करने की दी है सूचना

अब तक मार्केट में कोई वैक्सीन नहीं

पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस टीके के जरिये साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी-ए दोनों ही तरह के संक्रमण से बचाव का दावा किया है। भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भारतीय वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि की घोषणा की है। प्राइवेट कंपनियों के लिए जारी आवेदन में आईसीएमआर ने टीके के उत्पादन और आगे के परीक्षण शुरू करने की सूचना दी है। आईसीएमआर के अनुसार, टाइफाइड से बचाव के लिए अभी तक बाजार में कुछ टीके उपलब्ध हैं।

BRIEF NEWS

38 सीनियर डीएसपी को दी गई प्रोन्नति

RANCHI : झारखंड पुलिस के 38 सीनियर डीएसपी रैंक के अधिकारी को प्रोन्नति मिली है। इन सभी



डीएसपी को ग्रेड पे 6600 पुनर्रक्षित वेतनमान लेवल 11 में प्रोन्नति दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। प्रोन्नति पाने वाले में मजररूल होदा, अरुण कुमार बड़ाइक, समीर कुमार तिकी, बचनदेव कुजूर, रजत माणिक बाखला, सतीश चंद्र झा, पुष्पवोतम कुमार सिंह, केवी रमण, प्रमोद कुमार केसरी, संदीप कुमार गुप्ता, विकास चंद्र श्रीवास्तव, सुमित कुमार, राजा कुमार मित्रा, राज किशोर, अजीत कुमार विमल, चंदन कुमार वत्स, ज्ञान रंजन, कौशर अली, अमर कुमार पांडे, मनोज कुमार महतो, रणवीर सिंह, मनोज कुमार झा, अभिषेक कुमार, धीरेन्द्र नारायण बंका, ओमप्रकाश तिवारी, सुदर्शन कुमार आस्तिक, संजय कुमार, विजय कुमार महतो, दीपक कुमार, श्रद्धा केरकेट्टा, समीर कुमार सरीया, आनंद ज्योति मिंज, सुनील कुमार रजवार, दिलीप खलखो, जीतावाहन उराव, जयदीप लकड़ा, अजय केरकेट्टा और संजीव कुमार बेसरा शामिल हैं।

66 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ

RANCHI : केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लाभ झारखंड के 66 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, इस योजना के तहत सुसुविध निजी और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। नई बीमा अवधि में 534 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। पुराने पैकेजों के रेट को भी रिवाइड किया गया है। उच्च अंत प्रक्रियाएं, उच्च अंत दवा, और उच्च अंत निदान की प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। टीएमएस 2.0 वर्जन को लागू किया गया है। इससे अस्पतालों को काम करने में सुविधा मिलेगी।

मारवाड़ी युवा मंच ने की गौसेवा

RANCHI : बुधवार को मारवाड़ी युवा मंच, रांची शाखा ने हरमू रोड स्थित रांची गौशाला न्याय में गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सदस्यों एवं उनके परिवार वालों ने ताजा पालक, रोटी और गुड़ शिलाकर बिना दूध देने वाली निर्बल और असहाय गायों की सेवा कर पुण्य का लाभ उठाया। कार्यक्रम के संयोजक मंच के गौ सेवा प्रभारी युवा विशाल महेलका एवं युवा उज्जवल मुरारक का थे। उल्लेखनीय है कि मारवाड़ी युवा मंच रांची शाखा हर माह अपने सदस्यों एवं उनके परिवार वालों के लिए गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन करता है। मारवाड़ी युवा मंच के प्रवक्ता राखव जालान ने बताया कि कार्यक्रम में मंच के शाखा अध्यक्ष युवा आशीष अग्रवाल , सचिव सोनित अग्रवाल, उपाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, युवा अमित अग्रवाल एवं अन्य सदस्य अपने परिवार सहित उपस्थित थे।

रांची के डोरंडा थाना में तैनात सिपाही की मौत

RANCHI : राजधानी रांची के डोरंडा थाना में तैनात सिपाही गजेन्द्र कुमार यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह मूल रूप से गोण्डा जिले के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, गजेन्द्र कुमार यादव लंबे समय से बीमार थे और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे।

नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर बोलीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिकी अब तक सैकड़ों लोगों की मांडर रेफरल अस्पताल ने बचाई है जान

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने मांडर रेफरल अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मांडर रेफरल अस्पताल ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और यह अस्पताल क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। समय के साथ अस्पताल भवन का भी नवीनीकरण जरूरी था। आज 9 करोड़ 21 लाख 15 हजार रुपये की लागत से नए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। मंत्री ने इस भवन के उद्घाटन के साथ-साथ अस्पताल की उन्नति की दिशा में और भी प्रयास करने की बात कही। मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने कहा कि मांडर का नाम इस अस्पताल से जुड़ा है। लेकिन, यह अस्पताल न केवल मांडर बल्कि खलारी, बुड़मू, चान्हो जैसे

क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करता है यह हॉस्पिटल आवश्यकता के अनुसार समय के साथ अस्पताल भवन का जरूरी था नवीनीकरण



- 9 करोड़ 21 लाख 15 हजार रुपये की लागत से नए भवन का हुआ निर्माण
- अब उच्चतम स्तर के चिकित्सा उपकरणों की भी की जाएगी व्यवस्था

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविर का उठाया लाभ
बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इसके अलावा कृषि मंत्री वंडरलैंड स्कूल मांडर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुईं। कार्यक्रम ने स्कूली बच्चों

द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वै प्रभावित हुईं और उन्होंने बच्चों से अच्छे प्रदर्शन करने के अलावा भविष्य में अपने सपनों को पूरा करने की अपील की।

सभी लोगों का ध्यान रखना जरूरी

मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सभी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम और आप स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी संभव है। मेरा यह प्रयास हमेशा रहेगा कि इस अस्पताल को समय के साथ अपग्रेड किया जाए। इस दौरान उन्होंने बूढ़ा खुशरा स्थित सरकारी हाई स्कूल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में भी मंत्री ने भाग लिया। इस मेले में हड्डी रोग, नेत्र रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया। हमारा प्रयास यह है कि बाकी सभी उपचार यहां किए जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर बीमारियों के लिए लोग बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं।

माघ पूर्णिमा पर रांची के मंदिरों में रही भीड़

RANCHI : बुधवार को माघ पूर्णिमा पर राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह नहा धोकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। रांची के पहाड़ी मंदिर, जगरनाथपुर मंदिर, मेन रोड स्थित काली मंदिर, मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भीड़ देखी गयी। इस दौरान रांची के पुराण स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में पूर्णिमा में विशेष पूजा- पाठ और विशेष आरती का आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी सेवा बाम ट्रस्ट ने किया था। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का संचालन प्रणामी ट्रस्ट करता है। मंदिर के पुजारी अरविंद पांडे ने भगवान श्री राज श्याम जी को विधिवत पूजा- अर्चना कर भोग लगाया तथा पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराया। इसके बाद सामूहिक रूप से आरती की गई एवं प्रसाद वितरण किया गया। माघ ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल एवं प्रवक्ता संजय सराफ ने बताया माघ पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा- पाठ किया गया तथा भजन- कीर्तन में सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजन गाए।

कांग्रेस ने मनाई संत शिरोमणि गुरु रविदास की 648वीं जयंती मजबूत संगठन बनाने के लिए समाज को करना होगा जागरूक : केशव कमलेश

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 648 वीं जयंती कांग्रेस भवन रांची में प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से केदार पासवान की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गुरु रविदास से हमें सीखने की आवश्यकता है। खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके विचारों के अनुसार संगठित होकर समाज में आगे बढ़ने



की कोशिश करनी चाहिए। आज अनुसूचित जाति के लोगों को अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है, समाज का अन्य वर्ग उन्हें आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कोशिश उन्हें स्वयं करना होगा। समाज के मुख्य धारा में आगे रखने के लिए संविधान में उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों के बारे में उन्हें जानना

नेशनल गेम में लॉन बॉल के स्वर्ण पदक विजेता को विधायक ने दी बधाई



RANCHI : देहरादून में आयोजित नेशनल गेम 2025 में लॉन बॉल में झारखंड की ओर से खेलते हुए वसीम अकरम ने स्वर्ण पदक जीता। वसीम अकरम काफे की मिलत कॉलोनी निवासी काफे कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संजय खान के छोटे भाई हैं। लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद घर लौटने पर उनसे मिलने उनके प्रशंसकों की भीड़ जुट गई। काफे विधायक सुरेश कुमार बेदा भी वसीम के घर पहुंचे। विधायक ने वसीम को बधाई देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर अफजल मंसूरी, फिरोज अहमद, मो. शमीम, सरफराज खान, आमिर खान, बिन्दो साहू, गौरी शंकर महतो और शकील आजाद सहित कई लोग थे।

हेमंत सरकार ने लाभार्थियों के लिए खड़ी की समस्याएं झारखंड में अव्यावहारिक है आयुष्मान योजना का नया नियम : बाबूलाल मरांडी

PHOTON NEWS RANCHI :

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के आयुष्मान भारत योजना के नए नियम को लेकर कड़ी आलोचना की है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। लेकिन, राज्य सरकार के हालिया फैसले ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत एक नया नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक केवल 50 बेड (शहरी) और 30 बेड (ग्रामीण) वाले निजी अस्पताल ही



इस योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जो खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य स्रोत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे गरीब मरीजों को इलाज के लिए महंगे और दूर-दराज के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन होगा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से इस फैसले पर

रांची में तापमान औसत से अधिक, ठलाएगी गर्मी

RANCHI : राजधानी रांची में इस वर्ष भी गर्मी सताएगी। फरवरी माह में रांची में अधिकतम तापमान औसत से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी में यदि पिछले चार दिनों की बात की जाए तो बुधवार को यहां का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो औसत से 2.5 डिग्री अधिक है। वहीं मंगलवार को 2.5 डिग्री अधिक, सोमवार को 3.8 डिग्री अधिक, जबकि रविवार को राजधानी में औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस वर्ष रांची के अलावा राज्य के कई शहरों में भी से ही तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसमें सरायकेला, बाँखेला, जमशेदपुर, डाल्टेनगंज प्रमुख रूप से शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी से संभावना है कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी रांची में प्रचंड गर्मी पड़ी थी, जिससे आम जन जीवन परेशान हो गया था।

एक मंच पर जुटे आदिवासी मुंडा समाज के लोग व धार्मिक अगुवा

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को खूंटेरुटी मुंडा धर्म सभा और सरना संगेम खूंटी के आह्वान पर राज्यभर से एक मंच पर आदिवासी मुंडा समाज और धार्मिक अगुवाओं का महाजुलूस हुआ। इसमें ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम समेत स्थानीय सैकड़ों खोइहा मंडली शामिल हुईं। मुख्य पाहन अखंड पाहन के नेतृत्व में सैकड़ों पाहनों ने कोम्पाट और आदि शक्ति की विधिवत पूजा अर्चना संपन्न की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य का एकमात्र मुंडा जनजाति है, जिसके नाम से खतियान बना और छोटानागपुर का मुंडा जनजाति प्रकृति शक्ति का मुख्य

पुजारी है। मुंडा जनजाति पंचायत का प्रमुख होता है और गांव तथा पड़हा व्यवस्था का संचालन करने में निपुण होते हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज मुंडा समाज पर आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और व्यवसायिक तरीके से हमले हो रहे हैं। इसके लिए गांव, पंचायत, शहर और जिला स्तर पर मुंडाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक होना होगा। वहीं मुंडा समाज पर हो रहे हमलों को रोकना जा सकता है। मुंडा समाज की अपनी मुंडारी भाषा है, जो राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है, लेकिन आज तक इसे आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

पहले की अपेक्षा बाइक के लिए दोगुना और कार के लिए 50% अधिक देना पड़ेगा चार्ज

रांची नगर निगम बढ़ाएगा वाहनों की पार्किंग का शुल्क

PHOTON NEWS RANCHI :

अब अगर आप रांची नगर निगम के वाहन पड़ाव स्थल पर अपना वाहन खड़ा करेंगे तो अधिक चार्ज देना पड़ेगा। इस संबंध में नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। नई व्यवस्था में दो पहिया वाहन के लिए पांच के बदले 10 रुपये देने होंगे। इसी तरह चारपहिया वाहन वातक को 20 के बजाय अब 30 रुपये पड़ाव शुल्क देने होंगे। पड़ाव स्थल पर गाड़ी खड़ा करने वालों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी बहाल की जाएंगी। दोनों तरह के वाहनों के लिए तय शुल्क पहले तीन घंटे के लिए होगा। दस मिनट तक के लिए वाहन पड़ाव निःशुल्क होगा। इसके पहले दो पहिया वाहन के लिए प्रति तीन घंटा के लिए पांच रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 20 रुपये लगते थे। निगम द्वारा नए स्तर से बंदोबस्ती को लेकर संवेदक के साथ एकरारनामा होते ही बढी हुई दर प्रभावी हो जाएगी। निगम की ओर से ई-ऑफेशन के जरिए अभी 14 वाहन पड़ाव स्थल की बंदोबस्ती कर दी गई है। शेष 15 पड़ाव स्थल की जल्द ही बंदोबस्ती हो जाएगी।

जल्द लागू होगी नई व्यवस्था, कई तरह की सुविधाएं भी की जाएंगी बहाल पहले मोटरसाइकिल के लिए लगते थे ₹5 व चारपहिया वाहनों के लिए ₹20

बस स्टैंड की दुकानों का किराया बढ़ा

नए बंदोबस्तधारी के साथ एकरारनामा होते ही नया शुल्क प्रभावी हो जाएगा। ज्यादा शुल्क लेने और मनमानी की तत्काल शिकायत की जा सकेगी। टेकेदारों की मनमानी पर जांच के बाद रोक लगाई जाएगी। 15 वाहन पड़ाव स्थलों के लिए फिर से निविदा निकाली जाएगी। जानकारी के अनुसार, खादगढ़ा में बिरसा मुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में 15 एससी दुकान का किराया भी दस प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बढी दर पर ही उक्त दुकान का तीन साल के लिए नवीनीकरण किया गया है।



पार्किंग में मोटे अक्षरों में लगेगा सूचना पट्ट

रांची नगर निगम सभी पड़ाव स्थल पर नए सिरे से सूचना पट्ट लगाएगा। इसमें मोटे अक्षर में प्रशासक संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नहीं चलेगी मनमानी

शहर के 29 वाहन पड़ावों का ठेका लेने वाले बंदोबस्तधारी की मनमानी पर अंकुश के लिए निगम की ओर से पहल की गई है। अब किसी स्तर से वाहन खड़ा करने वालों के साथ मनमानी और बदसलूकी करना बंदोबस्तधारी को महंगा पड़ेगा। बंदोबस्तधारी के खिलाफ किसी तरह की शिकायत के लिए निगम में कोषांग बनेगा, जहां प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर टेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक, संजय कुमार ने कहा कि रांची नगर निगम के नियंत्रणधीन वाहन पड़ाव स्थल के शुल्क में लंबे समय के बाद मामूली वृद्धि की गई है।

स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल



PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप के मर्डर के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने जेल में बंद भोला सिंह, गौतम यादव, संजय सिंह, सुग्रीम सिंह, राजेश महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य और जांच के आधार पर कांड को सत्य बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है। इस हत्याकांड के आइओ (अनुसंधानकर्ता) ने कोर्ट में 51 गवाहों की सूची और अन्य साक्ष्य भी जमा किये हैं। इस हत्याकांड की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि घटनास्थल और आरोपियों के पास से पुलिस ने जो खोजा और

डीजल चोरों के गिरोह ने मारी थी गोली

बता दें कि पिछले वर्ष दो अगस्त को स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को डीजल चोर के गिरोह ने अंजाम दिया था। घटना की रात दारोगा बर्बडे पार्टी मनाकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान चोर किसी टैंकर से डीजल चोरी कर रहे थे। अपनी इशूटी निभाते हुए दारोगा ने रोक-टोक की तो डीजल चोर गिरोह उनसे उलझ गया और हत्या की घटना को अंजाम दिया।

गोलियां बरामद की थीं, वह एक समान है। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त अभियुक्तों ने ही सोची समझी साजिश के तहत सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या की।

सीसीटीवी कैमरे में कैद है लूटपाट करने वाले अपराधियों की तस्वीर



पूरी जानकारी दी, हालांकि जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती तीनों अपराधी फरार हो चुके थे। मामले में शिवचरण के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। इसके

अलावा रांची-टाटा रोड से गुजरने वाली सभी सड़कों पर चेक पोस्ट स्थापित कर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। रांची के ग्रामीण एसपी निमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा सीएससी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी मिलने पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है।

गैर पुलिसकर्मियों को भी दी जाएगी नए आपराधिक कानून की ट्रेनिंग

RANCHI : गैर पुलिसकर्मियों को भी नए अपराधिक कानून की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें डॉक्टर, नर्स, सहाय चिकित्सक आदि शामिल हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसएसपी और एसपी को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित डीजी एंड आईजी कॉन्फ्रेंस 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रत्येक जिला में गैर पुलिसकर्मियों को नये अपराधिक कानून के तहत अतीव भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है। ऐसे में अपने-अपने जिला में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए पुलिस मुख्यालय को जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे कर्मयोगी पोर्टल पर सभी अनुसंधान पथधिकारियों का निबंध सुनिश्चित करें।

मर्दर्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स की परीक्षा में लहराया परचम



PHOTON NEWS RANCHI :

राजधानी रांची में ब्राब्रे के जाहिर ग्राम स्थित मर्दर्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई)-2025 की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। स्कूल के छात्र हर्षवर्धन सिंह, श्रेयाश, दिव्याशु साहू, शौर्य गुप्ता, समीर गौतम, आदित्य अरुण, प्रांशु कुमार व

आदित्य कुमार ने जेईई मेन्स 2825 में क्वालिफाई किया है। सभी छात्रों ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों सहित स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्य को दिया। छात्रों की इस सफलता का स्कूल की प्राचार्य डॉ.रोमी झा व स्कूल के प्रबंध निदेशक अंबुज कुमार झा ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ इन जगहों पर घूमने जाएं, ट्रिप रहेगी यादगार

फरवरी का महीना लव बर्ड्स के लिए बेहद खास माना जाता है। फरवरी महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बनाते है। यदि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन रोमांटिक जगहों पर जरुर जाएं। यह ट्रिप आपको बेहद यादगार रहेगी।

फरवरी का महीना प्यार महीना कहा जाता है। इस महीने में वैलेंटाइन डे आता है, जो कि कपल इसे सेलिब्रट करते हैं। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन वीक शुरु हो जाएगा। इस खास महीने में लव बर्ड्स कहीं न कहीं घूमने का प्लान जरुर बनाते हैं। अगर आप भी फरवरी में अपने पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं और घूमने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आइए आपको बताते हैं कि आप किस रोमांटिक प्लेस पर घूमने जा सकते हैं।

दार्जिलिंग

फरवरी के महीने में घूमने के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि चाय के बागानों से घिरी हुई है। यहां पर टाइगर हिल में एक टॉय ट्रेन चलती है इसमें बैठकर आप सुंदर पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए यह जगह काफी अच्छी है।



महाबलेश्वर

अगर आप भी पार्टनर के साथ फरवरी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक अच्छी डेस्टिनेशन में से एक है। यह जगह हरे-भरे प्रकृति और सुकून भरे मौसम के साथ ही पहाड़ों के नजारे देख सकते हैं। झरने और झील देख सकते हैं। मुंबई के पास इस जगह पर लोग वीकेंड पर जाना काफी पसंद करते हैं।

गोवा

अगर आप फरवरी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ गोवा जा सकते हैं। यहां पर आप समुद्र के किनारे सनसेट का मजा ले सकते हैं। यहां पर घूमने कई जगहे हैं। गोवा में आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और आप समुंद्र किनारे अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं।

हम्पी

खुबसूरत नजारे के लिए हम्पी काफी फेमस है। यूनेस्को की विश्व धरोहर मानी जाने वाली यह जगह एक हनीमून के लिए भी सबसे बढ़िया है। यहां पर केले के बागान और बिखरी पहाड़ियां हम्पी शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक हो सकती हैं। हम्पी में घूमने के लिए काफी जगहें है।



ट्रैकिंग के शौंकिनों के लिए यह एक आदर्श स्थल है येलागिरी

येलागिरी की प्रमुख आकर्षणों में से एक येलागिरी झील है, जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर हरे-भरे बाग-बगिचे और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जो पर्यटकों को विश्राम और शांति का अहसास कराती है।

येलागिरी, तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा पर्वतीय स्थल है, जो चित्ताकर्षक प्राकृतिक दृश्यावलियों, शांतिपूर्ण वातावरण और रोमांचक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान विशेष रूप से उन पर्यटकों के लिए आदर्श है जो शहरी हलचल से दूर शांतिपूर्ण जगहों की तलाश में रहते हैं। यहां के हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत झीलें और सुरम्य ट्रैकिंग रूट्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं येलागिरी के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में।

1. येलागिरी झील

येलागिरी की प्रमुख आकर्षणों में से एक येलागिरी झील है, जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर हरे-भरे बाग-बगिचे और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जो पर्यटकों को विश्राम और शांति का अहसास कराती है। यहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी हैं, जो इसे परिवारों के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है।



2. स्वामीमलई हिल्स

स्वामीमलई हिल्स येलागिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। ट्रैकिंग के शौकिनों के लिए यह एक आदर्श स्थल है, क्योंकि यहां की चढ़ाई आपको अद्वितीय दृश्य और प्रकृति के नजारे प्रदान करती है। इसके ऊपर से आसपास के इलाके का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है।

3. पंगलिंगम झरना

येलागिरी के पंगलिंगम झरने में गिरते हुए पानी की आवाज और ठंडी हवा पर्यटकों को ताजगी का एहसास कराती है। यह झरना प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौंकिनों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहां पहुंचने के लिए कुछ ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, जो इस स्थान को और भी रोमांचक बनाती है।

4. जैन मंदिर

येलागिरी में स्थित जैन मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है और यहां के दर्शन करने से एक अलग ही अनुभव मिलता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है।

5. विलियानुर झरना

यह झरना येलागिरी के पास स्थित एक और लोकप्रिय स्थान है। यहां पर गिरते पानी के झरने के साथ-साथ आसपास की हरी-भरी वादियों का

दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इस झरने के पास घूमने और प्रकृति के नजारे का आनंद लिया जा सकता है।

6. येलागिरी पार्क

यह पार्क येलागिरी झील के पास स्थित है और यहां आप परिवार के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए खेलकूद के सामान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह स्थल विशेष रूप से परिवारों के लिए एक आदर्श गंतव्य है।

7. अक्टिविटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स

येलागिरी में कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग आदि। इन गतिविधियों के माध्यम से आप प्रकृति के करीब जाकर रोमांचक अनुभव ले सकते हैं।

8. जंगल सफारी

अगर आप जंगल और वन्यजीवों के प्रेमी हैं, तो येलागिरी के आस-पास के जंगलों में सफारी का अनुभव भी ले सकते हैं। यहां के घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

9. सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य

येलागिरी के पहाड़ों से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। यहां के पहाड़ी इलाकों में सूरज के निकलने और ढलने के समय के दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह दृश्य आपके लिए यादगार होगा।

येलागिरी एक शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है। यहाँ का वातावरण, झीलें, झरने, पहाड़ और ट्रैकिंग रूट्स आपको शांति और रोमांच का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करते हैं। यदि आप एक यात्रा प्रेमी हैं और प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना चाहते हैं, तो येलागिरी एक बेहतरीन गंतव्य हो सकता है।

इस सुरम्य पहाड़ी स्थल पर यात्रा करते हुए आप न केवल अपनी मानसिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं।



कोलकाता की इन 3 जगहों पर सेलिब्रेट करें बर्थडे, खास और यादगार बन जाएगा दिन

किसी खास जगह पर जाकर बर्थडे मनाकर लोग इसको एक यादगार पल बनाना चाहते हैं। हम सभी बर्थडे के दिन को खास बनाने के लिए खास लोकेशन की तलाश करते हैं। अपने किसी खास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना सबसे अनोखा एहसास होता है। कुछ लोग अपने परिवार या पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए किसी सुकून देने वाले जगह पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोलकाता की कुछ ऐसी फेमस जगहों के बारे में बताते जा रहे हैं, जहां पर आप बर्थडे पार्टी प्लान कर सकते हैं।

प्रिसेंप घाट

हुगली नदी के किनारे प्रिसेंप घाट का दृश्य और शांति से भरा माहौल आपके जन्मदिन को यादगार बना देगा। प्रिसेंप घाट की सुंदरता और ताजगी बर्थडे पार्टी के लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप अपने बर्थडे को अधिक यादगार बनाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर सनसेट का दृश्य देखते हुए बर्थडे पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। यह जगह सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ज्यादा सुंदर और बेहतरीन हो जाती है। कोलकाता की यह फेमस जगह घूमने के लिए काफी अच्छी है।

पार्क स्ट्रीट

अगर आप भी कोलकाता में बर्थडे पर घूमने के लिए पार्ट स्ट्रीट जाने का प्लान कर सकते हैं। यह कोलकाता के सबसे स्टाइलिश पर्यटक आकर्षणों में से एक है। जोकि फूड स्ट्रीट और नाइट लाइफ हब के लिए फेमस है। अक्सर लोगों को बर्थडे पार्टी राय या शाम के समय प्लान करना पसंद होता है।

इलियट पार्क

बता दें कि इलियट पार्क बैठने और आराम करने के लिए काफी अच्छी जगह है। शहर के केंद्र में स्थित यह पार्क बेहद शांत और हरा-भरा है। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण आपका दिल जीत लेगा। बर्थडे पार्टी के लिए आप इस जगह का चयन कर सकते हैं। आप यहां पर घंटों समय बिता सकते हैं। यह पार्क दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। ऐसे में आप इस बीच यहां आ सकते हैं। यह कोलकाता का सबसे सुंदर पार्क है। वहीं यह पार्क बच्चों के साथ घूमने के लिए बेहद अच्छी जगह है।



स्वर्ग से भी सुंदर इस जगह पर मिलेगा मानसिक सुकून, रहने-खाने में नहीं खर्च होंगे हजारों रुपए

आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाना बजट के अंदर होने के साथ ही आप प्रकृति के बीच समय भी बिता सकेंगे। यहां पर गंगा का कल-कल बहता ठंडा पानी, गंगा आरती, मंदिर, सुंदर घाट आपको मानसिक सुकून देगा।

घर और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालने के कारण लोग मशीन की तरह काम करते हैं। ऐसे में इस व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण लोग अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कई बार लोग काम का इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि शरीर थक जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में आपको फौरन एक ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि यह ब्रेक आपको मानसिक शांति देने के साथ अंदर से हील करने का काम करता है। इसलिए आपको काम से ब्रेक लेकर किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, जहां पर आप खुलकर सांस ले सकें और शांति व सुकून का अनुभव कर सकें। अगर आप भी किसी ऐसी जगह की

तलाश में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाना बजट के अंदर हो और आप प्रकृति के बीच समय भी बिता सकेंगे। दरअसल हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर पूरे विश्व भर से लोग योग सिखने के लिए आते हैं। यह जगह और कोई नहीं बल्कि ऋषिकेश है। यहां पर गंगा का कल-कल बहता ठंडा पानी, गंगा आरती, मंदिर, सुंदर घाट और चारों ओर योग व आध्यात्म का नजारा आपको मानसिक सुकून देने का काम करेगा।

इस तरह करें ऋषिकेश जाने की प्लानिंग

दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए आपको कई बस और ट्रेन मिल जाएंगी। बसों का किराया 300-400 रुपए के बीच होता है। इसके साथ ही ट्रेन के टिकट की कीमत भी करीब-करीब इतना ही होगा।

लोकल ट्रांसपोर्ट

दिल्ली से ऋषिकेश जाकर प्राइवेट कार या फिर कैब के इस्तेमाल की जगह लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्राइवेट कैब जहां आपको 200-300 रुपए खर्च करने होंगे। तो वहीं लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर आपका खर्चा 40-50 रुपए ही आएगा। बता दें कि आपको ऋषिकेश बस स्टॉप से कई

लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे।

आश्रम में रहें

आप ऋषिकेश में होटल की जगह हॉस्टल में स्टे करें। हॉस्टल की शुरुआत 500 रुपए से होती है। अगर आप राम झूला के पास हैं, तो आपको यहां पर कई आश्रम मिल जाएंगे।



स्ट्रीट फूड का लें मजा

अगर आप चाहें तो राम झूला के पास या लक्ष्मण झूला के पास खाने-पीने के लिए आपको मंहगे से लेकर बजट तक में कई पैकेज मिल जाएंगे। आप यहां पर स्ट्रीट फूड का भी मजा ले सकते हैं। आपको यहां पर 100 रुपए में खाने-पीने को काफी कुछ मिल जाएगा।



निराश करती है जनप्रतिनिधि अपराध मामलों में देरी



दशातां है कि सांसदों एवं विधायकों का अपने विरुद्ध मामलों की जांच या सुनवाई पर बहुत अधिक प्रभाव है और अपने राजनीतिक वर्चस्व एवं प्रभाव के कारण मुकदमे को पूरा नहीं होने दिया जाता है।

ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय अपने इस दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। समय-समय पर ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि एम्पी-एमएलए अदालतों को जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके। समझना कठिन है कि जिन अदालतों का गठन ही कुछ विशेष मामलों के निस्तारण के लिए हुआ है, वे उनको सुनवाई में प्राथमिकता का परिचय क्यों नहीं दे रही हैं? उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन अदालतों को यह स्पष्ट निर्देश दे कि वे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई एक निश्चित समय सीमा में करें और ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालयों को निर्देशित करें। यदि ऐसा कुछ नहीं किया जाता तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना बहुत कठिन होगा और आपराधिक छवि के नेताओं के मामले न्यायालयों में बढ़ते ही जायेंगे। यह स्थिति लोकतंत्र का उपहास उड़ाने वाली ही है। यह स्थिति अधिक चिन्ताजनक एवं दुःखद इसलिए भी है कि अब तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भी जमातें देने का सिलसिला कायम हो गया है। जनप्रतिनिधि भी रक्षक नहीं, भक्षक हो रहे हैं। ये कानून का भक्षण करने में माहिर होते जा रहे हैं। ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो पहले वोट मांगते हैं, फिर जीत के बाद लोगों को लात मारते हुए उनके साथ तरह-तरह के अपराध करते हैं। लोकतंत्र के मुखपृष्ठ पर

बहुत धब्बे हैं, अंधेरे हैं, वहां मुखौटे हैं, गलत तत्त्व हैं, खुला आकाश नहीं है। मानो प्रजातंत्र न होकर अपराध तंत्र हो गया। क्या यही उन शहीदों का स्वप्न था, जो फांसी पर झूल गये थे? राजनीतिक व्यवस्था और सोच में व्यापक परिवर्तन हो ताकि कोई भी अपराधों में लिप्त नेता जन-प्रतिनिधि न बन सके।

दिल्ली नगर निगम चुनावों में जीते पाषंदों के संदर्भ में एडीआर और हृदिल्ली इलेक्शन वाचहू ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी कर यह बताया गया है कि दो सौ अड़तालीस विजेताओं में से बयालीस यानी सत्रह प्रतिशत निर्वाचित पाषंद ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, उन्नीस पाषंद गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। इससे पूर्व दिल्ली में फरवरी, 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी एडीआर ने अपने विश्लेषण में चुने गए कम से कम आधे विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज पाए थे। इसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। अब प्रश्न है कि दिल्ली नगर निगम हो या विधानसभा चुनावों में भी आप पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए स्वच्छ छवि के व्यक्ति को तरजीह देने की जरूरत क्यों नहीं समझी? जबकि इस पार्टी का घोष ही रहा अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति।

चुनावी सुधारों पर होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहता है। राजनीति का अपराधीकरण-ह्राअपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेनाहू-हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। मौजूदा लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक 29 प्रतिशत सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली

लोकसभा में यह आँकड़ा तुलनात्मक रूप से कम था। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, किंतु इस संदर्भ में किये गए सभी नीतिगत प्रयास समस्या को पूर्णतः नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। हालांकि एक अच्छी पहल यह हुई है कि अब हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सरकार किसी भी सांसद एवं विधायक के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं ले सकती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह स्थिति समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करती है। वैसे तो भारत का लोकतंत्र बड़े-बड़े बाहुबली एवं अपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं के शर्मनाक कृत्यों का गवाह रहा है, बार-बार शर्मसार हुआ है। यही कारण है कि राजनीति का चरित्र गिर गया और साख घटती जा रही है।

इन वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं वे चुनाव अर्हता, योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर न होकर, व्यक्ति, दल या पार्टी के धनबल, बाहुबल एवं जनबल के आधार पर होते रहे हैं, जिनको आपराधिक छवि वाले राजनेता बल देते रहे हैं। आप ने भ्रष्टाचार एवं अपराधों पर नियंत्रण की बात करते हुए राजनीति का बिगुल बजाया। लेकिन यह दल तो जल्दी ही अपराधी तत्वों से घिर गया। नेताओं की चादर इतनी मैली है कि लोगों ने उसका रंग ही काला मान लिया है। अगर कहीं कोई एक प्रतिशत ईमानदारी दिखती है तो आश्चर्य होता है कि यह कौन है? पर हल्दी की एक गाँठ लेकर थोक व्यापार नहीं किया जा सकता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा संकट है। आदर्श लोकतंत्र एवं समाज व्यवस्था का निर्मित करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं पर है, जिनका चरित्र एवं साख मजबूत होना जरूरी है। दुःखद स्थिति है कि भारत अपनी आजादी के अमृत काल तक पहुंचते हुए भी स्वयं को ईमानदार नहीं बना पाया, चरित्र सम्पन्न राष्ट्र नहीं बन पाया।

(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

महाजाम की जटिल व्यवस्था

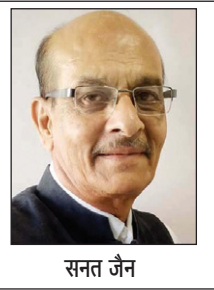
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। 144 साल बाद पड़ रहे इस महाकुंभ में आने के रास्तों में महाजाम लग गया है। तीन सौ किमी. लंबे जाम को दुनिया का सबसे बड़ा जाम बताया जा रहा है। यह विशेष पर्व ज्यों-ज्यों अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं में इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से प्रयागराज के मार्ग पर दस किमी. लंबा जाम है। रीवा-चित्रकूट से आने वाले मार्ग पर तकरीबन सत्रह किमी. तो भदोही से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्ते पर पंद्रह किमी. और मिर्जापुर से आने वाले मार्ग पर बारह किमी. का महाजाम लगा है। जिला व पुलिस प्रशासन के सारे दलों की धूम्रियां उड़ाने वाले इस जाम में फंसे प्यासे-भूखे और परेशान लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। बिखलते नन्हे बच्चों और बीमार-बुजुर्गों के परिवार रंगते वाहनों में ट्रैफिक अरेस्ट से जूझने को मजबूर हैं। फ्रांस में भारी बर्फबारी के चलते 1980 में 175 किमी. लंबे जाम को सबसे बड़े जाम के रूप में याद किया जाता है। 2010 में बीजिंगझतिब्बत हाईवे पर लगे सौ किमी. के जाम से निकलने में दस दिन लग गए थे। मगर

यह न तो प्राकृतिक आपदा है, न ही अचानक लगा जाम है। सरकारी दलों और व्यवस्था को लेकर तमाम प्रचार के खोखलेपन का उपहास बन रहा है। भगदड़ और बार-बार आग लगने के पीछे लापरवाही छिपी नहीं है। लखनऊ, सुलतानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, आजमगढ़ से अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी यातायात बुरी तरह प्रभावित है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को आवागमन के लिए बंद करने के आदेश को अपरातफरी के बाद इसे अफवाह ठहरा कर लीपापोती की गई। जाहिर है, इससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है। स्थानीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों पर बात नहीं हो रही है जबकि उनकी दिनचर्या भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, उन्हें घरबंदी में जीना पड़ रहा है। शहर और सड़कों की क्षमता का अनुमान लगाए बगैर भव्य आयोजन और करोड़ों की धन राशि उड़ाने का उद्देश्यहीन योजना की जितनी निंदा की जाए कम है। श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों को बरालाने और छद्म प्रचार से महाकुंभ के साथ महाजाम के संगम को झुठलाने से हकीकत को बदला नहीं जा सकता।

चिंतन-मनन

आध्यात्मिक आकाश का प्रकाश

चिन्मय आकाश में न तो सूर्यप्रकाश की आवश्यकता है, न चन्द्रप्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक- सूर्य, ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के (जिन्हें वैकुण्ठ कहा जाता है) चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। इस तेज का एक अंश महत-तत्त्व अर्थात् जगत से आच्छादित रहता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह भौतिक जगत रूपी मिथ्या, विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही मुक्त हो जाता है। तब वह यहां वापस लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेर का पापद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्णभावनाभावि होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए, जो कृष्णभावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवद्भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। यहां परमं मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में जगत का कोना-कोना भगवान की सम्पत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और छह ऐसेरे से पूर्ण है। कठोपनिषद् में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्यप्रकाश, चन्द्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आन्तरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं।



सनत जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी भ्रष्ट आचरण कानून पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। ट्रंप के इस आदेश के बाद विदेश में व्यापार या ठेका हासिल करने के लिए अब अमेरिकी कंपनी द्वारा रिश्तत देना अपराध नहीं होगा। अभी तक अमेरिकी कानून के अनुसार यह एक बड़ा अपराध था, जिसके कारण अमेरिकी सरकार अथवा अमेरिका की कंपनियां जो सारी दुनिया के देशों में जो व्यापार करती थी, इस कानून से यह संदेश जाता था, अमेरिका की कंपनियां अन्य देशों में रिश्तत नहीं देती हैं। जिसके कारण अमेरिका की सरकार और अमेरिकी कंपनियों की साख पूरी दुनिया के देशों में बनी हुई थी। लूके-छुपे तौर पर यदि कोई कंपनी या व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करता था, ऐसी स्थिति में अमेरिकी कानून के अनुसार उसे आर्थिक तथा आपराधिक मामलों में सजा से दंडित किया जाता था। ट्रंप ने जो निर्णय अभी लिया है, उससे सारी दुनिया के देशों में यह संदेश गया है। अमेरिका की कंपनियां अपने लाभ के लिए दुनिया के किसी भी देश के राजनेता, अधिकारियों या कारोबारियों को रिश्तत देकर ठेका हासिल कर सकती हैं। रिश्तत देकर सामान खरीदने-बेचने के कटिक्ट हासिल कर सकती हैं।



प्रमोद भार्गव

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ और बक्सर योद्धाओं के संयुक्त दल ने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 31 नक्सली मार दिए। बीजापुर में सात दिन में यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले गंगालुर क्षेत्र में 2 फरवरी को 8 नक्सली मारे गए थे। इसी तरह 4 अक्टूबर 2024 को सुरक्षा बलों ने अबुझमाड़ के थुलथुली में 38 नक्सलियों को मार गिराया था, लेकिन अब नक्सलियों को बालों लगातार चुनौती मिल रही है। नक्सलियों का दमन हो रहा है।

केंद्र सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने का संकल्प लिया हुआ है। बावजूद नक्सलियों का अस्तित्व अब तक बना है तो इसलिए क्योंकि कुछ देश विरोधी ताकतें उन्हें धन, घातक हथियार, विस्फोटक और उत्तम गुणवत्ता की संचार प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं। लगता है कि सजातीय वनवासियों और ग्रामीणों पर उनकी पकड़ अभी भी



अमेरिका के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों को इस निर्णय से सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। किसी भी देश में अमेरिका की कंपनियों से व्यापार या कारोबार किया जाएगा, वह सभी शक के दायरे में होगा। जिन देशों के कारोबारी या सरकारें अमेरिकी कंपनियों से खरीददारी करंगी, उन्हें भी शक की निगाह से देखा जाएगा। ट्रंप का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है, जबकि अमेरिकी कानून के अनुसार भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी सहित आठ लोगों के ऊपर अमेरिका में अपराधिक मामला दर्ज है। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका की कोर्ट में 2200 करोड़ रुपए की घूस के मामले में गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं। वारंट जारी होने के बाद से गौतम अडानी अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं। उनका व्यवसाय पूरी दुनिया में प्रभावित हुआ है। गौतम अडानी ने अमेरिकी कानून से

बचने के लिए वहां के सांसदों को अपनी पैरवी में उतारा था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अडानी को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी राजनायिक और कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले भारत सरकार ने जिस तरह से आयात-निर्यात व्यापार में अमेरिका के पक्ष में शुल्क को घटाया है, वह सब अडानी समूह की राहत से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी की राजनेता के स्थान पर एक कारोबारी के रूप में पहचान है। दोनों ही अपने निजी कारोबार एवं फायदे को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार के निर्णय कर रहे हैं। गौतम अडानी और भारतीय कारोबार पर एलन मस्क की भी नजर है। डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के प्रयास में लगे

नक्सलवाद : निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़सुता देश

बनी हुई है। उधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि या तो नक्सली समाज से जुड़ जाएं या खाले के लिए तैयार रहें। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अत्याचारवाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका है, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुखाबलों को लगा पाना

मुश्किल होता है, लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के माददगर्जों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध 'सलवा जुद्ध' को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से ठन गई। इस हमले में कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है।



दरअसल, देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उसकाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रीयताी बुद्धिजीवी पुछ्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की। माओवादियों के खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगाता दिखाई दे रहा है।

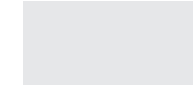
Flawed policies have ravaged Manipur

Manipur Chief Minister N Biren Singh, who is under scrutiny for his alleged role in inciting the violence that has plagued the state over the past 21 months, resigned on February 9 following a meeting with Union Home Minister Amit Shah. The prolonged unrest has not only led to rape, murder and destruction of property on a large scale but also scarred the psyche of the Manipuri people.

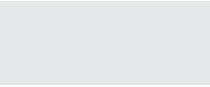
The startling quandary of the situation came to the fore recently when Shah claimed that the North-East was once “known for terrorism, infiltration, blockade, drugs, armed trafficking, corruption and national disturbances.” He added that “today, it is known for development, connectivity, infrastructure, education, investment and agriculture development.” He also highlighted the fact that Central ministers had visited the region over 700 times during the past decade. Virtually addressing an event where appointment letters were given to youths in Agartala (Tripura), he claimed that PM Narendra Modi as well as the Union and state governments were fully committed to Tripura’s welfare. There was no word on a similar commitment to Manipur’s welfare. Shah earlier met the CM’s critic, Panchayati Raj Minister Y Khemchand Singh, and Manipur Assembly Speaker Thokchom Satyabrata Singh. Party MLAs had unequivocally told Satyabrata that more than two-thirds of them were not happy with the current leadership. Calling the turmoil intolerable, they said they could not wait anymore and were going to make some move in the interest of the public and the state. Laying emphasis on the restoration of peace and normalcy, they threatened that something big and unprecedented would happen during the upcoming Assembly session if course correction was not done before that (the session, which was set to commence on February 10, was eventually declared null and void in the wake of Biren’s resignation). They also contradicted Shah, who had said in Tripura’s context that 2,800 youths getting jobs was an epochal event.

The disquiet and violence since May 2023 repeatedly raised doubts about Biren’s leadership, but the party high command, including the PM and the Home Minister, were not inclined to remove him. In the meantime, bickering within the state party unit kept growing. Ten Kuki-Zo MLAs declared their intent to boycott the Assembly session. The BJP’s allies, the Naga People’s Front and the Janata Dal (United), withdrew support from the state government. Taking advantage of the political crisis, the main Opposition party, the Congress, planned to move a no-confidence motion during the session. The report of the recently appointed Governor Ajay Bhalla, who recently superannuated as Union Home Secretary and is well aware of both the political as well as the law and order situation, must have played a key role in the matter. Things took an intriguing turn when Biren was accused of having played a role in inciting ethnic violence. The Kuki Organisation for Human Rights Trust moved the Supreme Court, alleging that there were audio tapes that established the CM’s complicity. The SC has referred the tapes to the Central Forensic Science Laboratory (CFSL), giving it six weeks to submit a report. Meanwhile, an analysis conducted by Truth Labs Forensic Services, a private non-profit organisation, has revealed that there is “93 per cent probability” that the voice in the leaked tapes is of Biren. If the CFSL report matches the Truth Labs findings, it will have a huge impact not only on the politics of the state but also at the national level. Biren had been acting at the instance of the BJP high command and the Union Government, which was clear from the fact that despite the carnage that stirred the national conscience, neither the party nor the Centre showed any inclination to remove him — till their leaders’ heads could no longer remain above water.

Apart from exerting pressure to get him removed, the Opposition planned an attack on the Central BJP leadership, even as Biren pursued the Modi-Shah politics of Hindutva and unified the Meiteis under this umbrella, while the RSS played a role too



How promises to clean Yamuna can translate into action



If all the STPs and CETPs in Delhi were to function as designed and planned, the state of the Yamuna would massively improve in the city.

THE Yamuna river figured prominently in the just-concluded Delhi Assembly elections. After the BJP’s victory, Prime Minister Narendra Modi assured Delhi that the new government would make every effort to clean the river. “It may be a long haul, but Mother Yamuna will surely bless our efforts,” he said. Will this help the cause of the river? There is a lot that the Delhi government can do to improve the state of Yamuna. Flow and connectivity are the defining characteristics of any river. The Delhi government can work to ensure that the Yamuna has sufficient freshwater flow downstream from the Wazirabad barrage, where there is none today.

There is also a need to improve the different kinds of connectivity that define the river: longitudinal (between upstream and downstream at various points within Delhi); lateral (between the river and its tributaries and the floodplains); and vertical (for groundwater recharge). On the pollution front, three key areas that need attention are: sewage treatment and performance of sewage treatment plants (STPs); performance of central effluent treatment plants (CETPs) to treat industrial effluents; and proper management of solid waste since a lot of solid waste ends up in rivers when not managed properly. But the Yamuna exists beyond Delhi and the state of the river upstream and downstream has an impact on the state of the river within Delhi. So, for all the above issues, Delhi needs to work with the upstream and downstream states. The Central government has a huge role to play here. The way the Centre deals with the river has a bearing on each of the above aspects of Yamuna. Since the Yamuna is the biggest tributary of the Ganga, the National Mission for Clean Ganga can make a huge impact on its fate. So too can the Union Ministry of Environment and Forests, Jal Shakti Ministry — including the Central Water Commission and the Upper Yamuna River Board — the Union Ministry of Housing and Urban Affairs (which has the Delhi Development Authority under it) and the Central Pollution Control Board. Unfortunately, these central agencies have not performed well enough to give the Yamuna a new lease of life in Delhi.

Delhi has a very high sewage treatment capacity (around 760 million gallons per day) as compared to other cities in India. And yet, the Yamuna is in bad shape in Delhi. The key reason is that the STPs and CETPs are not functioning as designed. The governments have installed STPs with large capacity at huge expenditure but failed to ensure that the plants function as planned. There is no transparency, accountability or participatory management in the governance of the STPs. No one knows why the STPs are not functioning as planned, nor are there any consequences when STPs do not function as planned. If the government is really interested in improving the state of the Yamuna, it needs to address the



governance of the STPs and CETPs. If all the plants in Delhi were to function as designed and planned, the state of the Yamuna would hugely improve in the capital. Sewage, that is a curse now, would become a boon for Delhi as treated sewage can replace freshwater for a number of activities, thus also reducing the demand for freshwater and freeing some freshwater for Yamuna’s environment flows. For this, rainwater and local water bodies within Delhi can be used in the way Bengaluru is doing. Rejuvenated water bodies within Delhi can harvest rainfall. In the post-monsoon months, adequately treated sewage can be released in such water bodies, which will help treat it further and also recharge groundwater. The outgoing AAP government had started this process and it can be taken to the next level.

In fact, the new government in Delhi needs to achieve much better rainwater harvesting, which, in turn, can help decrease the demand for freshwater from the Yamuna and, thus, free up some additional water for environment flows in Delhi. It can ensure that all government buildings, parks, roads, bridges, metro stations, schools, colleges, malls, multiplexes, embassies, etc must have functioning rainwater harvesting systems and some of them can also recharge groundwater. The sponge effect of these functioning rainwater harvesting systems would also reduce the floods in Delhi during the monsoons and make rainwater available post monsoon. It will also have an exemplary demonstration effect of functioning

rainwater harvesting systems for others to emulate. The improved state of the river in Delhi will be a boon during Chhath puja and other festivals, it will improve micro-climate and also create a much-needed scenic, peace-giving place for the city dwellers. The state of the Yamuna in Delhi is also affected by the following: dams and diversions of the water; the state of pollution in the river; its flow and connectivity; sand-mining; groundwater use and recharge; state of local water bodies and wetlands; aquatic and terrestrial biodiversity; state and extent of natural forests and state of tributaries of the Yamuna upstream and downstream of Delhi. The pattern and quantum of rainfall and snowfall in the Yamuna basin and the state of glaciers in the upstream are also relevant here. Thus, the Yamuna puzzle has many components. A Delhi water policy can be a key instrument to provide guidance on these issues.

The new government in Delhi can, through the involvement of people, prepare such a policy. Importantly, the BJP is also in power in other Yamuna basin states like Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttarakhand. The AAP and the Congress must act as a responsible Opposition in the Delhi Assembly and Parliament and keep the Yamuna issue alive. A lot can and must be done to improve the state of Yamuna in Delhi. The challenge of climate change must also be considered. Let us see what the new government actually does.

Too little, too late

Manipur CM’s resignation not enough



Amid the euphoria over its resounding win in the Delhi elections, the BJP has started the process of repairing its battered double engine in strife-torn Manipur. Chief Minister N Biren Singh has finally stepped down, over a month after he tendered a public apology and expressed regret over the deaths and displacement caused by the unrest in the northeastern state. If Biren thought he had done enough to save his chair merely by saying sorry, he was proven wrong. The last straw was the leak of some audio tapes, which include telephonic conversations that purportedly lay bare his role in inciting ethnic violence. All eyes and ears are on the Central Forensic Science Laboratory, which has been ordered by the Supreme Court to verify the authenticity of the tapes and submit a report next month. In a bid to pre-empt possible embarrassment and outrage, the BJP

has prodded Biren to put in his papers. This is practically an escape route for him, considering the gravity of the allegations against him. Much damage

has already been done, and his resignation has come too late in the day. Ethnic violence has claimed over 250 lives in Manipur since May 2023, with both the Central and state governments failing to handle the volatile situation. Biren remained in the saddle even when Imphal burned, while the party top brass kept ignoring the growing clamour for his ouster. What’s worse, Prime Minister Narendra Modi has chosen to stay away from the state, giving the impression that Manipur is just a blip on the Centre’s radar. A new CM will not make much of a difference on the ground as long as there is a lack of political will to resolve the conflict and bring the perpetrators to book. The people of Manipur are impatiently awaiting justice and peace. The onus is on the Modi government to regain their trust.

Delhi verdict reshapes political equations

While one electoral defeat, especially when fighting a two-term incumbency, does not mean the demise of a party, it is obvious that the people’s belief in AAP’s promise of alternative politics is over.

The verdict of the Delhi Assembly elections has implications not only for the Aam Aadmi Party (AAP) but also for the INDIA bloc and the role of freebies in electoral politics. The elections saw the AAP, the BJP and the Congress compete with one another over offering monetary rewards, subsidised utilities and free public transport for different segments of society. Such strategies being resorted to by the parties underscore the debate between the transient effectiveness of monetary incentives and programmatic politics.

In search of electoral dividends, parties of all hues, when in power, have been shying away from long-term investment of public resources in such primary sectors as education, health, infrastructure, housing and employment generation, which is far more effective in addressing the issues of poverty and deprivation.

Worse, these populist schemes are often personalised as ‘guarantees’ in the name of the party leader, promoting person-centred leadership, much to the detriment of intra-party democracy. Also, such tall promises are made knowingly, even when the economy of the state concerned is in a precarious condition, which is often the case. The election verdict raises questions about the AAP’s future. While one electoral defeat, especially when fighting a two-term incumbency, does not mean the demise of a party, it is obvious that the people’s belief in AAP’s promise of alternative politics is over. The party, which emanated from the Anna Hazare movement, initially contested elections on the promise of fighting corruption in high places, ending VIP culture and bringing the government nearer to the people. However, over time, it has degenerated into just another political party, having all the vices afflicting other parties. The AAP leadership has been facing allegations of corruption to generate electoral funds,

doing away with intra-party democracy, promoting sycophancy and personal loyalty and adopting the lavish lifestyle of the average political leadership of India. All this has led to a disillusionment among the middle class with the AAP, especially with Kejriwal, who dominated the party. The results show that the AAP has even suffered a decline in the support of lower classes living in underdeveloped colonies and slums despite having provided lots of benefits to them. This can be attributed to the politics of patronage and clientelism that the party promoted. With the top AAP leaders facing serious corruption charges and being restrained by the judiciary, the beneficiaries of AAP’s schemes shifted their loyalties to the BJP, which has promised even larger ‘benefits’ to them. The Delhi elections also raise questions about the future of the INDIA bloc in view of the fact that some Samajwadi Party and Trinamool Congress leaders openly campaigned for AAP candidates and not for Congress nominees. Additionally, the Congress and the AAP contested the poll separately, with the leaders of the two parties levelling allegations against each other.

It is obvious from the results that if the AAP and Congress had fought as allies, it would have certainly helped the AAP win a few more seats, including some of its top leaders. The impression is that the Congress and the BJP are on the same page as far as the agenda of decimating the AAP is concerned. The AAP’s decline means a gain for the Congress in Punjab and Delhi. And, for the BJP, it means doing away with a competitive party which not only aims to corner the lower and lower middle class social support base but also plays the softer

version of Hindutva politics. The results also show the importance of the Congress. Despite its decline, apart from the BJP, the Congress is still the only other ‘polity-wide’ party. This as an important factor in any coalition arrangement against the formidable BJP. It was evident

delivery overlaps between various government units, creating difficulty in fixing accountability in the eyes of citizens. The contentious role of the centrally appointed lieutenant-governors over the period was another formidable factor that came in the way of governance.



during the Jharkhand Assembly elections. It would be fair for the AAP to argue that the unique administrative structure of Delhi came in its way of effectively running the state despite enjoying the popular mandate in the past. A multitude of authorities causes jurisdictional issues and complicates policy formulation, coordination and implementation, especially since the AAP and the BJP were at loggerheads with each other. The responsibility for developmen work and service

The party state leadership should be alert about a bleak electoral future if it does not take immediate corrective action. The apprehension that the Delhi-based AAP leadership would interfere more in state government affairs may be misplaced as the autonomy of the state unit of the party is likely to increase. If attempted so by a desperate high command, it would be disastrous for the AAP, as regionalism is a strong factor in the identity politics of Punjab.

No reduction in funds for asset creation, effective capex to increase by 18%: FM

NEW DELHI. The government has not reduced the allocation to capital expenditure, but instead has increased the effective capital expenditure by about 18% from Rs 13.18 lakh in the current fiscal to Rs 15.48 lakh crore in FY26, which is 4.3% of GDP, finance minister Nirmala Sitharaman said in parliament on Tuesday.She was replying to the debate on Budget 2025 in Lok Sabha. Addressing the concern raised by many members over the shift in focus away from capex, the minister reiterated that capital outlay has not come down at all.The finance minister also said that while the effective capital expenditure in FY26 is 4.3% of the GDP, 10 basis points lower than the budgeted fiscal deficit of 4.4%.
“The government intends to use about 99% of borrowed resources to finance effective capital expenditure in the upcoming year,” she said in the Lok Sabha.She also highlighted the Narendra Modi government’s efforts to maintain fiscal prudence over the past 10 years and yet manage to achieve high economic growth. Comparing the present government’s efforts with that of UPA, the FM said that while the 2008-09 financial crisis left us among the fragile five economies, India has emerged stronger fiscally after once-in-a-century pandemic like Covid in 2020-21.She also pointed out the efforts of the Modi government to maintain fiscal transparency by bringing off-budget borrowings of certain central government agencies like Food Corporation of India (FCI) on the government books.
Allaying the fears of states over transfers of resources from the Centre, the finance minister highlighted the fact that transfers to the states would cross Rs 25.01 lakh crore across all schemes in FY26, which is Rs 2 lakh crore more than revised estimate for the current financial year.“Transfer of resources is growing by the year,” she reiterated by citing that transfers to states in 2020-21 was Rs 13.44 lakh crore, which has risen to Rs 25 lakh crore over five years. She expressed confidence that the Indian economy is seeing a “speedy rebound” from 5.4% growth clocked in the second quarter of the current fiscal.

Saluja moves HC against Sebi, REL, JM Fin

NEW DELHI. Rashmi Saluja, recently ousted by the shareholders of Religare Enterprises (REL), has filed a plea before the Delhi high court against capital market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi), the company (REL) itself and JM Financial for non-compliance, violations of RBI conditions and suppressing a competing open offer, among other things.
Saluja alleged that the Sebi didn’t take the necessary action to protect investors and minority shareholders in the open offer process. The plea stated that the RBI granted conditional approval for the open offer on December 9, 2024, requiring the acquirers (Burmans) to consolidate their non-banking financial companies and submit a detailed plan within 90 days. Saluja alleges the acquirers have failed to meet these conditions and that Sebi has allowed the open offer to proceed despite this non-compliance.

Vi narrows loss to Rs 6,609 cr; ARPU rises to Rs 173 in Dec

NEW DELHI. Vodafone Idea (Vi), India’s third-largest telecom service provider, has narrowed its loss to Rs 6,609 crore in the third quarter of FY25. The telco had posted a net loss of Rs 6,986 crore in the same period in FY24.Revenue for the quarter rise by 1.7% to Rs 11,120 crore. It reported its highest cash EBITDA since the merger at Rs 2,450 crore, a year-over-year (YoY) growth of about 15%. Debt from banks fell by Rs 5,290 crore over the last year and stood at Rs 2,330 crore.“With the recent equity infusion of `191 crore from one of our promoters, we have secured Rs 26,000 crore in fresh equity capital over past 10 months. In parallel, we continue to engage with lenders for debt financing, aligning with our planned network expansion investment of Rs 50,000–Rs 55,000 crore over a three-year period. The government’s decision on the bank guarantee waiver underscores



its ongoing support for the telecom sector, a critical pillar of Digital India’s future,” said Akshaya Moondra, CEO, Vi.Average revenue per user (ARPU) rose to Rs 173 in Q3FY25 from Rs166 in the previous quarter, a 4.7% rise. The telco reported a major expansion of its 4G population coverage, adding nearly 41 million people to reach 1.07 billion by the end of December 2024, up from 1.03 billion in March 2024.Vi is on track to achieve its 4G population coverage target of 1.1 billion by March 2025 and plans to further increase it to 1.2 billion, covering about 90% of the population.
The company will launch its commercial 5G services in Mumbai in March, followed by Delhi, Bengaluru, Chandigarh, and Patna in April 2025.

Will retail inflation cool down further in January Here's all you need to know

The RBI mentioned continued reduction in rice prices and sharp corrections in the prices of vegetables, especially in the prices of onions, potatoes and tomatoes, in its January 2025 Bulletin.

NEW DELHI. The country’s retail inflation is likely to witness a dip in January 2025, bringing relief to consumers, as per economists polled by Reuters.The poll predicts consumer inflation in January to sharply drop to 4.60%, a five-month low from December’s 5.22%. This decline is attributed to slowing food price rises, particularly in cereals, milk, vegetables, pulses, and sugar, as mentioned by the Reserve Bank of India (RBI) in its January 2025 Bulletin.The RBI



mentioned continued reduction in rice prices and sharp corrections in the prices of vegetables, Especially in the prices of onions, potatoes and tomatoes, in its January 2025

Bulletin. On the other hand, the prices of edible oils and wheat remain higher.Meanwhile, the central bank announced a reduction of 25 basis points in the repo rate from 6.5% to 6.25% in its

L&T Chairman SN Subrahmanyan blames welfare schemes for labour shortage in India

NEW DELHI. Larsen & Toubro Chairman and Managing Director SN Subrahmanyan has raised concerns over the declining migration of construction labourers in India, attributing it to the availability of government welfare schemes and a growing preference for comfort.
Speaking at CII’s Mystic South Global Linkages Summit 2025 in Chennai, Subrahmanyan spoke about the difficulties faced by the construction industry in hiring and mobilising workers.“As an organisation, we employ about 2.5 lakh staff and 4 lakh labourers at any given point of time. While attrition among staff does bother me, I am more worried about the availability of labourers today,” Subrahmanyan said, according to Business Today.Labour is not willing to move for opportunities... Maybe their local economy is doing well, maybe it is due to the various government schemes & DBTs (direct benefit transfers) available to them, but they are not willing to move,”he added.
It may be noted that L&T employs a dedicated HR team to oversee labour

mobilisation, recruitment, and deployment. However, Subrahmanyan admitted that despite these efforts, finding and retaining



workers remains a growing challenge.His comments come at a time when India’s infrastructure sector is facing an increasing shortage of skilled and semi-skilled workers, which could impact the pace of project execution across the country.Subrahmanyan also pointed out that reluctance to migrate for work is not limited to blue-collar workers. “When I joined L&T as a graduate engineer, my boss said if you are from Chennai, you go to

Delhi and work. But today, if I ask a person from Chennai to work out of Delhi, he says bye. It’s a different world of work today, and we have to see how to make HR policies flexible,” he said.The L&T boss had previously sparked controversy by calling for a 90-hour workweek, drawing criticism from employees and industry observers. “I regret I am not able to make you work on Sundays. If I can make you work on Sundays, I will be more happy, because I work on Sundays,” he said in an earlier statement.“What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? Come on, get to the office and start working.”His comments reignited discussions on workplace culture, employee well-being, and changing attitudes toward work-life balance in India’s corporate sector.As the labour market evolves, companies like L&T may need to rethink their strategies for attracting and retaining both blue- and white-collar workers in an era where mobility and work expectations are shifting rapidly.

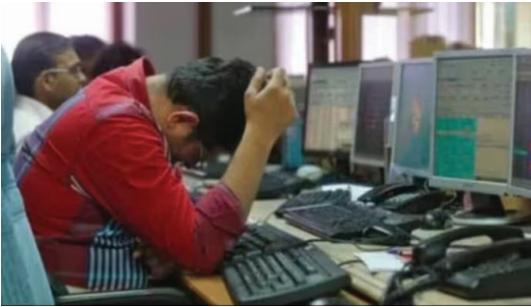
Fixed Medical Allowance Extended For THESE Central Govt CGHS Pensioners: How Much Money Is Given Per Month Check Eligibility, Benefits

New Delhi. The Department of Pension & Pensioners Welfare (DoPPW) under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in its Office Memorandum released on 7 February 2025 has announced that it is extending the benefit of Fixed Medical Allowance (FMA) to the Central Government civil employees covered under the National Pension System (NPS) on their retirement from service and who are eligible for CGHS facility but are residing outside CGHS area as per the applicable rate, if they do not avail any CGHS facility or avail only the IPD facility under CGHS.
"The above instructions also include prescribed forms and formats for claiming the benefit of FMA by above employees. These forms and formats

have been revised including PRAN details in these forms / formats as per the reference received from the office of Controller General of Accounts vide their ID note No. TA-3-6/3/2020-TA-IIIPart(1)/11948/412 dated 18.12.2024. Revised Forms /Formats to be used for the above purpose are enclosed with this O?," said the DoPPW OM.It has also been clarified in the OM that the rate of FMA prescribed for Central Government employees retired under NPS is equal to the rate of FMA granted to Central Government employees covered under old pension scheme i.e. Rs 1000 per month.However, the release of FMA into the account of the Central Government employee retired under NPS had been prescribed vide OM dated 06.12.2023 on quarterly basis

through the respective bank.
The OM has further clarified that the release of FMA for the period September to November shall be in the first week of December. However, the release of FMA from the month of December onwards shall be subject to submission of life Certificate by the beneficiary.Fixed Medical Allowance (FMA) is admissible to the Central Government civil pensioners/family pensioners (i) residing in areas not covered under Central Government Health Scheme or any corresponding Health Scheme administered by other Ministries/Departments and (ii) not availing OPD facility under CGHS. FMA is disbursed to the pensioners by the Pension Disbursing Authorities/Banks along with their monthly pension.

NEW DELHI. Benchmark stock market indices continued their poor run on Wednesday after crashing in the previous session, which led to a loss of Rs 10 lakh crore for investors.The S&P BSE Sensex nosedived 834.39 points to 75,459.21 at 10 am, while the NSE Nifty50 fell 251.95 points to trade at 22,819.85.It may be noted that the market capitalisation of BSE-listed companies reduced by as much as Rs 6 lakh crore. Most of the broader markets also fell during early trade as fears over the impact of US trade tariffs and weak Q3 earnings continued to erode investor confidence.
Analysts have already indicated that the volatility in the stock markets could persist as long as there is uncertainty over how US tariffs impact global trade. The uncertainty seems to have accelerated the pace of selling by foreign institutional investors (FIIs) as well and this has significantly impacted the mood on Dalal Street.
Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services, said, "Trump’s tariff tantrums have been impacting the markets for the last several days. Trump moving away from



targeting specific countries like Mexico, Canada and to a lesser extent China, and moving to import tariffs on steel and aluminum on all countries, has aggravated the concerns.""The European Union’s declaration that they will retaliate with counter tariffs has raised the probability of a full blown trade war. How this will pan out remains to be seen," he added.He highlighted that it is important to understand that President Trump, however powerful he might be, cannot manipulate the laws of economics."When higher tariffs raise inflation in the US and the Fed responds hawkishly, the US stock market will crash. This will restrain Trump. But it will take some time. Meanwhile, the drama and the volatility in the market will continue," Vijayakumar said, adding that investors can utilise the current weakness in the market to switch from the mid- and small-caps, which are even now overvalued, to the fairly valued largecaps.

Gail’s Dhabol LNG port set for all-weather ops, gas imports to get leg-up

NEW DELHI. The Dhabol LNG Port, owned and operated by national gas major Gail, is set for major capacity augmentation with the 2.3-km-long breakwater, which will be ready by end-March, making it an all-weather port.
Called Konkan LNG (KLL which is the terminal operator), the current terminal handles only 27% or 22 ships a year as against the designated capacity of 5 million tonne per annum or 18 million metric standard cubic meter per day (mmscmd) of natural gas per day, as the port can be operated only before and after the monsoons, rendering its operational for around seven months.
When the breakwater, being built by L&T since 2020 at an estimated cost of `720 crore, is expected to complete by end-March and commissioning by June after getting statutory clearances, the tanker handling capacity will rise to 30 ships immediately and then to 80 ships per annum when the ambient air heating facility will be ready by December 2026, Tony Mathew, chief executive of Konkan LNG, told TNIE.Currently, the facility uses seawater based heating system for regasification and the `580 crore ambient air heating facility will make it achieve

full capacity, said Mathew, who has been involved in almost all cross-country gas pipeline projects of Gail, particularly the most challenging ones in Kerala and Orissa.After completio of the breakwater project all statutory clearances from the Navigational Safety in Ports Committee and the Maharashtra Maritime Board for declaring the terminal an all-weather port, situated at Dhabol in the Ratnagiri district of Maharashtra will take two-three months. The port has a natural draught of 18 meters.Of the total energy requirement of 13,258 terra watt-hours, only 6.5% is met through natural gas now and government plans to take this mix to 15% by 2030.Total natural gas intake was 51 mtpa in FY24, of which domestic gas was 27 mtpa and the imports were 24 mtpa of Gail shipped 13.8 mtpa. The uniqueness of the Dhabol breakwater is that unlike many other breakwaters, this is an island facility, making its construction far more challenging. It is built at a seabed depth of 17-18 meters, rising to 7 meters above the water level and over 100 meters at base width, and a crest width of 7.35 meters. The breakwater is coming up 2.75 km off the shore or 750 meters from the present jetty/berth built by Enron, which also built 500 m of the breakwater on

2001.The project originally planned for completion by 2022 got delayed because of it being an island facility, construction could be done only in the non-monsoon season, the pandemic, a litany of litigations and the cyclone Tauktae in May 2021 which washed away construction



materials being other reasons, Mathew said, adding apart from large boulders being used for the breakwater, 22-30,000 tonne each of concrete blocks called accropodes are also used to dissipate wave energy. Each of the accropodes are placed inter-locked and checked with Echoscropy and physically by divers.The project is built by L&T Heavy Civil Structure Construction under the supervision of the

state-run Engineers India.Mathew said the gas intake from the present facility is only a third of the installed capacity as the NTPC-operated Dhahol Power Plant with an installed capacity of 1,960 mw across three turbines is running at very low capacity utilization as natural gas is costly now, forcing KLL to reduce its regasification capacity to only 7.5 mmsmd as against the designed capacity of 18 mmscmd, which is only 27% of the installed capacity. Not having the desired length of the breakwater also leads to lower utilization.This will be resolved when Gail sets up an ambient air heating system (AAHS) at an investment of Rs 580 crore. KLL will shortly invite civil tenders for this, Mathew said, adding once the breakwater is completed the terminal will achieve 41% of the designed capacity of 5 mtpa (80 cargoes/year) and will achieve 100% capacity after completion of the AAHS expected by December 2026.Konkan LNG is also going for expansion of the terminal from 5 mtpa to 6.3 mtpa in the second leg of the first phase with an estimated expenditure of Rs 1,100 crore by 2030, which will enable to handle 100 cargoes per year and.

CPWD urges departments to prioritise use of recycled C&D waste

The remark was made in a review meeting held to check the progress of usage of recycled material by the director general of CPWD and joint secretary, the Ministry of Housing and Urban Affairs.

NEW DELHI. With government agencies in Delhi-NCR failing to meet the target set for using construction and demolition (C&D) waste recycled products, the Central Public Work Department (CPWD) has asked all departments to ‘take pride’ in consuming reprocessed waste generated from construction, renovation, and demolition of concrete structures such as houses, roads, and bridges. The remark was made in a review meeting held to check the progress of the usage of recycled material by the director general (D-G) of CPWD and the joint secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).

Following the deliberation on low take-off of the C&D waste material by the Delhi Development Authority (DDA), National Building Construction Corporation (NBCC) and CPWD, the officials agreed

to introduce mandatory provisions for usage of 20 per cent recycled sand and other aggregates — conforming to the specifications of the Bureau of Indian Standards (BIS)—in tenders to achieve the target.

The manufacturers of pre-cast tiles are also to be mandated for using 20 percent recycled materials from C&D plants as per the specifications. According to the minutes of the meeting seen by this newspaper, quarterly demand of C&D recycled waste material should be shared in advance with the operators of the plants for planning and scheduling plant operations by the contractors.

“Government department start taking pride in using recycled materials and share in annual and sustainability reports,” read the minutes.

Instructions were also issued to all officials



concerned to upload details of utilizations of recycled material on the dedicated module every month.

In December, the ministry conveyed its displeasure to the CPWD as it had failed to meet the off-take target of utilisation of C&D waste products for three consecutive years. It noted that ‘overall performance of the department has been

poor over the preceding years due to lack of will, vision and action plan. The department, in its response, cited imposition of the Graded Response Action Plan (GRAP) in the national capital as one of the reasons for not achieving the target.

The government has been pushing for increased consumption of recycled C&D waste products such as paver blocks, Kerb stones, blocks, paver tiles, recycled aggregates, and manufactured sand under its flagship programme Swachh Bharat Mission (SBM).

20 percent recycled sand

The officials agreed to introduce mandatory provisions for usage of 20 per cent recycled sand and other aggregates — conforming to the specifications of the Bureau of Indian Standards (BIS) — in tenders to achieve the target.

Delhi traffic cops collected Rs 46 crore from 74 lakh violations in 2024, House told

NEW DELHI. Delhi Traffic Police issued over 74 lakh challans and notices in 2024, collecting Rs 46.29 crore in fines, Union Minister of State for Home Nityanand Rai informed the Lok



Sabha on Tuesday. In response to a written query on traffic violations across different categories, Rai stated that the city police issued 23.09 lakh challans and 51.41 lakh notices for various traffic offences during the year. While challans are issued on-site by traffic personnel, notices are generated online through automated traffic violation detection cameras, he added.

Over the past five years, the highest revenue from traffic violations was recorded in 2020, when Rs 213 crore was collected. That year, the police issued 10.99 lakh challans and 85.94 lakh notices. The second-highest collection was in 2021, amounting to Rs 98.45 crore, with 13.23 lakh challans and 66.03 lakh notices. In 2022, the revenue stood at Rs 74.46 crore with 14.69 lakh challans and 59.87 lakh notices. The collections declined to Rs 40.31 crore in 2023, despite issuing 17.26 lakh challans.

Key reasons behind violations

“The Delhi Police has informed that the main reasons behind the reported increase in traffic violations are an rise in vehicular traffic, lack of awareness among commuters and stricter enforcement of rules,” Rai said.

Constitution hatred, Rama Rajya vow: Decoding outfit that attacked Telangana seer

NEW DELHI. The Rama Rajyam extremist right-wing group, that allegedly attacked a prominent liberal temple priest based in Hyderabad, has dangerously wild ideas about how India should be run. It aims to overthrow the Constitution, persecute judges for their judgments, and set up its flawed version of Rama Rajya in Telangana and Andhra Pradesh through private armies. Its founder, Veera Raghava Reddy, and five others have been arrested by the Telangana Police for attacking Rangarajan, the priest of Balaji Temple, in Chilkur in Rangareddy district on February 7. In a statement, the priest’s father and convener of the Temple Protection Movement MV Soundararajan said the attackers targeted the priest because he refused to associate with their mission. On his YouTube channel named ‘Rama Rajyam’, Reddy regularly posts fiery videos against judges, policemen, alleged occupation of temple land and slaughter of cows. “If given the chance, I will burn the Constitution!” reads the translated version of the caption of one of his videos originally posted in Telugu.

The website of the Rama Rajyam was registered in 2022. As per the site, the organisation aims to establish a parallel system of administration based on the principles of the Bhagavad Gita. The outfit alleges that the current criminal justice system protects the wealthy and is against the poor and innocent, and aims to change that but doesn’t specify how. Reddy describes himself as a member of Lord Rama’s clan “Ikshvaku” and vows to retake land that he believes belongs to his clan and six sects of Hinduism.

The recovery of temples and temple land has been a common theme of Reddy’s videos. He ran a campaign to recruit around 5,000 people from Andhra Pradesh and Telangana in what he calls the “Rama Rajyam army” between September and December last year. A notification on its website promised a monthly salary of Rs 20,000 along with food and accommodation. Eligibility? Anyone with Class 10 (pass or fail), belief in Bhagavata Ramayana shlokas with “minimal understanding” can be a member.

"No Guarantee You'll Return": Indrani Mukerjea Cannot Travel Abroad

New Delhi. The Supreme Court on Wednesday dismissed the plea of Indrani Mukerjea, who is accused of killing her daughter Sheena Bora, challenging a Bombay High Court ruling that denied her permission to travel abroad.

A bench of Justices MM Sundresh and Rajesh Bindal directed the trial court to conduct the proceedings in the case within a year. Opposing the permission, the counsel for the CBI said this is a sensitive matter and



trial has come halfway and 96 witnesses have been examined.

The counsel appearing for Mukerjea, a former media executive, submitted that she has been given bail by the top court and there are 92 witnesses still to be examined in the matter.

She said the trial court has been vacant for the last four months and the proceedings may take a long time to conclude. The travel restriction matter came up in the Supreme Court after a special court on July 19 allowed Ms Mukerjea’s plea to visit Spain and the United Kingdom for 10 days over the next three months. The CBI approached the high court challenging the order passed by the special court. The high court quashed the special court’s order on September 27. Ms Mukerjea moved the top court challenging this high court order.

CBI Arrests 6 Delhi Transport Officials in Major Post-Election Corruption Crackdown

New Delhi. In a sweeping post-Assembly election crackdown, the Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested six officials from the Delhi Transport Department on charges of corruption and bribery, sources confirmed on Wednesday. The arrests come after multiple complaints alleging widespread corruption within the department, prompting the CBI to launch an undercover surveillance operation to verify the claims before taking decisive action.



According to CBI insiders, their investigation revealed prima facie evidence of bribery at multiple levels within the transport department. “The corruption was systematic, extending across various offices. The officials in question were engaging in illicit transactions related to vehicle registrations, permits, and fitness certificates,” a senior CBI officer told The Indian Express, requesting anonymity.

This marks the first major anti-corruption action by the CBI since the Assembly elections concluded, where the Aam Aadmi Party (AAP) suffered a stunning defeat, paving the way for the Bharatiya Janata Party (BJP) to return to power after 27 years. The BJP clinched 48 out of 70 seats, reducing AAP to 22 seats, while Congress remained at zero for the third consecutive election.

No discrimination against Rohingya children for school admissions: Supreme Court

NEW DELHI. No child will be discriminated against in education, the Supreme Court said on Wednesday while fixing for next week a plea seeking a direction to the Centre and the Delhi governments to grant Rohingya refugees in the city access to public schools and hospitals. The court just wants to know where these Rohingya families are living, in whose house and what their particulars are, a bench of Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh said while making no discrimination in education point.

Senior advocate Colin Gonsalves, appearing for the NGO Rohingya Human Rights Initiative, said he has filed an affidavit giving the details and pointed out that the Rohingya refugees have UNHCR (United Nations High



Commissioner for Refugees) cards. It will be easier for the NGO to give the particulars if these Rohingya families have these cards, Justice Surya Kant said. Gonsalves then sought some time to furnish more details to the court.

The top court posted the matter for further hearing after 10 days. On January 31, the top court asked the NGO to apprise the court where the Rohingya refugees have settled in the city and the facilities

accessible to them. It also asked Gonsalves to file an affidavit indicating their places of settlement in Delhi.

Gonsalves said the NGO sought access to public schools and hospitals for Rohingya refugees as they were denied access due to lack of Aadhaar cards. “They are refugees having UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) cards, and therefore they can’t have Aadhaar cards. But for want of Aadhaar they are not being granted access to public schools and hospitals,” he submitted. Gonsalves said Rohingya refugees resided in Shaheen Bagh, Kalindi Kunj and Khajuri Khas areas of Delhi. “In Shaheen Bagh and Kalindi Kunj they are residing in slums and in Khajuri Khas they are residing in rented accommodation,” he had submitted.

Mumbai reports first death due to Guillain-Barre Syndrome, state toll reaches 8

The 53-year-old man was admitted to Nair Hospital on January 23 with weakness and was shifted to the ICU.

NEW DELHI. A 53-year-old man died due to Guillain-Barre Syndrome (GBS) at a Mumbai hospital on Tuesday, marking the city’s first fatality due to the rare nerve disorder. With this, the total death toll due to G B S in Maharashtra has increased to eight. A resident of the Wadala area, the 53-year-old man was admitted to Nair Hospital on January 23 with weakness in his legs. He was employed as a ward boy in a hospital and was shifted to the Intensive Care Unit (ICU). The man was then placed on a ventilator due to breathing difficulties, reports said.

Diagnosed with GBS, he received

appropriate treatment at Nair Hospital but passed away on February 11. Mumbai reported its first case of GBS on February 7 after a 64-year-old woman, a resident of Andheri (East), was

health department till February 11, a total of 192 people have been suspected to have contracted GBS. A total of 172 cases GBS cases have been confirmed and a total of seven deaths have been reported so far due to the disease. Most cases are from Pune and surrounding areas.

As per information, 40 cases are from the Pune Municipal Corporation area whereas 92 are from the newly added villages of the PMC area. 29 cases have been reported from Pimpri Chinchwad whereas 28 GBS incidents have come from the Pune Rural area. Eight cases have been reported from other districts.

According to the Health Department of Maharashtra, 104 patients have been discharged so far, whereas 50 of them are in the Intensive Care Unit (ICU). The other 20 are on the ventilator.



diagnosed with the nerve disorder. Sharing an update on GBS, the Maharashtra Health Department said five new cases were recorded in the state today. As per the Maharashtra

Delhi HC orders unified App for public washroom complaints

The MCD, in its status report, claimed that a third-party audit found the condition of public toilets to be “satisfactory.”

NEW DELHI. With an aim to address the persistent issues plaguing public toilets in the national capital, the Delhi High Court has directed the Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), and New Delhi Municipal Council (NDMC) to develop a single, unified application to streamline complaints related to malfunctioning public restrooms. A division bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Tushar Rao Gedela has mandated a meeting between DDA acting V-C and the Municipal Commissioners of NDMC and MCD to explore the feasibility of the common platform. “We expect all three agencies to make earnest efforts in developing a unified application to ease the process of lodging and addressing grievances,” the bench asserted. The matter is listed for



further hearing on April 9. The directive was issued while hearing a PIL filed by Jan Sewa Welfare Society, which highlighted the deplorable state of public urinals in Delhi, citing inadequate water supply, poor hygiene, and lack of proper maintenance. The MCD, in its status report, claimed that a third-party audit found the condition of public toilets to be “satisfactory.” It also informed the court that a dedicated mobile app had already been launched to facilitate complaint

registration. However, the court was not convinced and directed the MCD to ensure wider publicity of the app through newspapers and other mediums. It also ordered that clear signage be put up at every public toilet, informing users about the complaint mechanism. Acknowledging the critical role of sanitation in public health, the court emphasized that a single integrated platform for grievances would significantly enhance accessibility and efficiency. “A unified app used by MCD, NDMC, and DDA would simplify the complaint process, ensuring faster redressal of grievances,” the bench noted. The plea underscores the urgent need for inspection, maintenance, and expansion of public toilet facilities across Delhi, warning that poor sanitation poses serious health risks and contributes to an

unsanitary urban environment.

Also in court

HC lists Rashid’s bail plea on Feb 24

The Delhi High Court on Tuesday listed for hearing on February 24 a plea by jailed MP Abdul Rashid Sheikh alias Engineer Rashid on the issue of lack of a forum to decide his bail plea in a terror funding case. Justice Vikas Mahajan deferred the hearing after he was informed by the counsel for the high court administration that the Supreme Court on Monday clarified that the NIA court dealing with the case could hear the bail plea.

Farmers’ stir: Look out circular junked

The Delhi High Court has quashed the look out circular issued against two men in relation to the 2021 farmers’ protest saying they fully cooperated in the investigation. Justice Sanjeev Narula on January 31 said there was no specific order from a judicial authority directing the the men to remain within the country and continuation of the lookout circular (LOC) was “arbitrary and excessive”.

NEWS BOX

SpaceX Rocket Carrying 23 Starlink Satellites Illuminates Night Sky Over California

World. In a spectacular night-time spectacle, SpaceX's Falcon 9 rocket illuminated the skies over Southern California on Monday as it soared into low-Earth orbit from Vandenberg Space Force Base in Santa Barbara County. The launch, which carried 23 Starlink satellites into orbit, was originally scheduled for Sunday but was delayed by a day. Residents across the West Coast of North America were treated to a spectacular display as the rocket's fiery trail blazed across the night sky. Videos and pictures shared on X showed the rocket's fiery plume leaving a trail as it ascended. The Falcon 9 rocket lifted off from Vandenberg Space Force Base at 9:09 pm EST on February 11. The Falcon 9's first stage returned to Earth about eight minutes after liftoff as planned, touching down in the Pacific Ocean on the SpaceX drone ship "Of Course I Still Love You." Space.com reported. According to the outlet, 23 Starlink satellites were part of SpaceX's ongoing mission to provide high-speed internet to remote and underserved areas globally. The launch marked the 445th mission for SpaceX. The company has now launched 18 Falcon 9 missions in 2025, with 12 of them Starlink flights. The Starlink satellite constellation currently has more than 6,900 operational spacecraft, the outlet reported. Also Read | Potentially Habitable "Super-Earth" Discovered Just 20 Light-Years Away Since its first launch in 2018, SpaceX has placed approximately 7,000 Starlink satellites in orbit, each measuring 9.2 feet in length, 4.6 feet in width, and 0.7 feet in thickness. The company aims to expand this network to 42,000 satellites in the coming years. Notably, while SpaceX continues its Starlink expansion, it recently faced a setback with its Starship prototype. On January 16, a Starship upper stage broke apart minutes after launch from Texas, forcing airline flights over the Gulf of Mexico to reroute due to falling debris. The spacecraft lost communication eight minutes after liftoff, prompting SpaceX Communications Manager Dan Huot to confirm an anomaly. Video footage captured bright orange debris streaking across the sky over Haiti, leaving trails of smoke behind.

Turkey Issues Fake Alcohol Warning After More Than 100 People Die From Poisoning In Tourist Hotspots

World. Turkey has issued a warning to avoid bootleg alcohol in the country after around 103 people were reported to have been fatally poisoned in two major cities since the new year. According to the Independent, all deaths happened in Ankara and Istanbul, after authorities warned about a rising death toll tied to an increase in illegal alcohol being sold disguised as big-name brands. In Istanbul, 70 people have died since January 14, and in Ankara, 33 have died since January 1. Across the two cities, another 230 were hospitalised in connection with the poisoned "booze" with 40 of those in critical condition, officials said. In Turkey, the price of alcohol has spiked in the last few years due to heavy taxes imposed by President Tayyip Erdogan's ruling AK Party. Alcoholic drink makers have also faced an increasingly onerous tax burden and other restrictions, the outlet reported. Moreover, the Turkish government has again hiked taxes on alcohol and tobacco products for 2025 on 3 January. This high cost has pushed some consumers, shops, restaurants and bars to rely on bootleg alcohol and homemade drinks, leading to rising poisoning in recent years. Istanbul's governor's office last month said it had taken steps to combat bootleg sales and distribution, including mandatory cameras at shops selling alcohol, suspending or revoking sale licences, and carrying out regular inspections. Authorities have arrested 13 people in Ankara and 11 others in Istanbul. They have also reportedly seized 102 tons of methanol and ethanol in Ankara, and over 86,000 litres of bootleg pr smuggled alcohol in Istanbul, as per The Independent.

Indian-Origin Woman Racially Abused On UK Train By Drunk Passenger: "We Conquered India"

World. A disturbing incident of racial abuse occurred on a train travelling from London to Manchester, where a 26-year-old Indian-origin woman was subjected to a vicious racist tirade by a reportedly intoxicated man. The ordeal began on Sunday when Gabrielle Forsyth was heading home and engaged in a friendly conversation with a fellow passenger, mentioning her work with a charity that supports immigrants. However, the conversation took a dark turn when a fellow passenger, who was drinking from a can, overheard her comment and became threatening and abusive, Metro reported. A video of the incident, which has now been deleted captured the man's racist and xenophobic rant, as he shouted at Ms Forsyth and boasted about England's historical conquests. He also launched a vile tirade at fellow train passengers calling them "immigrants". "You're in England, you are claiming something. You would not be in England if you weren't claiming something. English people conquered the world and gave it back to you. We conquered India, we didn't want it, we gave it back to you," he said in the video. "A lot of countries like that. Sorry about your f***ing sovereignty or whatever it is you are. Record me cause I'm recording you," he further said. Towards the end of the video, the man told her, "I am not gonna hit you, I have a girl there that lives to get hit. She ain't getting hit right now."

Jordan to take 2,000 sick Gaza kids as Trump pushes takeover plan

WASHINGTON. Jordan's King Abdullah II on Tuesday told Donald Trump that his country would take in some 2,000 sick children from war-torn Gaza, as the US president pushed his plan to take over the territory and push out Palestinians. Speaking at the White House, Abdullah added that Egypt would present a proposal on how countries in the region could "work" with Trump on the plan, despite Arab nations and the Palestinians having rejected it outright. "I think one of the things that we can do right away is take 2,000 children, cancer children who are in a very ill state, that is possible," Abdullah said as Trump welcomed him and Crown Prince Hussein in the Oval Office. Trump called it a "beautiful gesture" and said he didn't know about it before the Jordanian monarch's arrival at the White House. The US president meanwhile backed down on a suggestion that he could withhold aid for Jordan and Egypt if they refused to take in more than two million Palestinians from Gaza. "I think we'll do something. I don't have to threaten that, I do believe we're above that," Trump said. Trump stunned the

Israel threatens to restart war in Gaza if hostages are not returned by Saturday

JERUSALEM. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu on Tuesday said Israel would resume "intense fighting" in Gaza if Hamas did not return hostages by Saturday noon, without specifying whether he was referring to all captives. "If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end, and the IDF (Israeli military) will resume intense fighting until Hamas is decisively defeated," Netanyahu said in a statement issued after a meeting with his security cabinet. Israel's far-right Finance Minister Bezalel Smotrich also called on the prime minister to "open the gates of hell" on Hamas if the Palestinian militant group failed to release all hostages by Saturday. In a statement, Smotrich urged Prime Minister Benjamin Netanyahu to "inform Hamas unequivocally: Either all the hostages are released by Saturday -- no more phases, no more games -- or we open the gates of hell on them." Hamas said Monday — and reiterated Tuesday — that it planned to delay the release of three more

world when he announced a proposal last week for the United States to "take over" Gaza, envisioning rebuilding the devastated territory into the "Riviera of the Middle East" -- but only after resettling Palestinians elsewhere, with no plan for them ever to return. Jordan's Abdullah was repeatedly pressed by reporters on whether he supported the plan, but said only that Egypt was coming up with a response and that Arab nations would then discuss it at talks in Riyadh. "The president is looking at Egypt coming to present that plan... (then) we will be in Saudi Arabia to discuss how we should work with the president and with the United States," Abdullah said. "The point is, how do we make this work in a way that is good for everybody." Tough guy The meeting came as the Gaza ceasefire appears increasingly fragile, after Trump warned on Monday that "all hell" would break out if Hamas fails to release all hostages by Saturday. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Tuesday said Israel would resume "intense fighting"

hostages after accusing Israel of failing to meet the terms of the ceasefire, including by not allowing enough tents and other aid into Gaza. Earlier Tuesday, an Israeli official said Netanyahu ordered the army to add more troops in and around the Gaza Strip. Netanyahu also ordered officials



“to prepare for every scenario if Hamas doesn’t release our hostages this Saturday,” according to the official, who spoke on condition of anonymity to discuss a private meeting. So far, Hamas has released 21 hostages in a series of exchanges for hundreds of

South Sudan Is World's Most Corrupt Country, Denmark Least. India's Rank Is...

World. Denmark is the least corrupt country in the world followed by Finland, Singapore and New Zealand, according to the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2024, which serves as a barometer of public sector misconduct worldwide. The report compiled by Transparency International placed India at 96th spot, three positions down from the previous year's rank. The index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption according to experts and business people, using a scale of zero to 100, where "zero" is highly corrupt and "100" is very clean. The 2024 report highlighted that corruption is a dangerous problem in every part of the world, but a change for the better is happening in many countries. As per the list, in 2024, India's overall score was 38 while it was 39 in 2023 and 40 in 2022. India's rank in 2023 was 93. Among India's neighbours, Pakistan at 135th position, and Sri Lanka at 121st spot grappled with their respective low rankings. Bangladesh's ranking stood further down at 149,

while China ranked 76. Many countries had their worst showing in more than a decade, including leading powers such as the United States and France to authoritarian nations such as Russia and Venezuela. The US dropped from 69 points to 65 and landed in the 28th position from 24th place earlier. Other Western nations on the decline included France, which slid four points to 67 and five places to 25th; and Germany, which dropped three points to 75 and six places to 15th. It tied with Canada, which was down one point and three places. Mexico also dropped five points to 26 as the judiciary failed to take action in major corruption cases, Transparency International said. Russia, which already declined significantly in recent years, shed another four points to 22 last year. Transparency International noted that Moscow's full-scale invasion of Ukraine in February 2022 has "further entrenched authoritarianism." It said that Ukraine, while its score dipped one point to 35, "is making strides in judicial independence and high-level corruption prosecutions."

South Sudan slid to the bottom of the index with just eight points, displacing Somalia although the latter country's score dropped to nine. They were followed by Venezuela with 10 and Syria with 12. Transparency International noted that "global corruption levels remain alarmingly high, with efforts to reduce them faltering" in 2024. While 32 countries have significantly reduced their corruption levels since 2012, there is still a huge amount of work to be done as 148 countries have stayed stagnant or gotten worse during the same period. Corruption's Effect On Climate The group also pointed to worldwide risks from corruption to efforts to combat climate change. It said that a lack of transparency and accountability mechanisms increases the risk of climate funds being embezzled or misused, while "undue influence," often from the private sector, obstructs the approval of ambitious policies, hindering progress in reducing emissions and adapting to the unavoidable effects of global heating.

Nearly everyone in the world breathes bad air. This is what you can do to lower your risk

HANOI (Vietnam). Everyone loves a breath of fresh air. Unfortunately, too often our air is anything but fresh. While air quality varies dramatically from place to place and day to day, nearly the entire world — about 99% of the global population — is exposed to air at some point that doesn't meet the strict standards set by the World Health Organization, the agency has reported. Polluted air, laden noxious gasses or tiny, invisible particles that burrow into human bodies, kills 7 million people prematurely every year, the U.N. health agency estimates. And for the millions living in some of the world's smoggiest cities — many of them in Asia like New Delhi; Dhaka, Bangladesh; Bangkok and Jakarta, Indonesia — bad air might seem inescapable. But there are things that people can do, starting with understanding that the air isn't only polluted when it looks smoggy, said Tanushree Ganguly of the Energy Policy Institute of Chicago in India. “Blue skies can’t guarantee you clean air,” she said. What are the most dangerous kinds of air pollutants and their sources? Air pollutants often come from people burning things: Fuels such as coal, natural gas,

diesel and gasoline for electricity and transportation; crops or trees for agricultural purposes or as a result of wildfires. Fine, inhalable particles, known as particulate matter, are among the most dangerous. The tiniest of these — known as PM 2.5 because they are less than 2.5 microns in diameter — can get deep into human lungs and are mostly created by burning fuels. Coarser particles, known as PM 10, are linked to agriculture, roadways, mining or the wind blowing eroded dust, according to the WHO. Other dangerous pollutants include gases like nitrogen dioxide or sulfur dioxide, which are also produced from burning fuels, said Anumita Roychowdhury, an air pollution expert at the Center for Science and Environment in New Delhi.

The sources and intensity of air pollution varies in different cities and seasons. For instance, old motorbikes and industrial boilers are major contributors to bad air in Indonesian capital Jakarta while burning of agricultural waste is a major reason for air pollution spikes in cities in Thailand and India. Brick kilns that burn coal adds to



in Gaza if Hamas did not meet the deadline. Trump said he doubted that the Palestinian militant group would abide by the ultimatum. "I don't think they're going to make the deadline personally. I think they want to play a tough guy, but we'll see how tough they are," Trump said. But he played down the risk of a longer threat to efforts to create a lasting peace between

Israel and Hamas. "It's not going to take a long time when you know bullies," he added, referring to Hamas. The Jordanian king and crown prince earlier met Trump's National Security Advisor Mike Waltz. King Abdullah is a key US ally but last week rejected "any attempts" to take control of the Palestinian territories and displace its people after Trump stunned the world with his proposal for Gaza. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, who is expected to visit the White House later this week, urged on Tuesday the reconstruction of Gaza "without displacing Palestinians." Analysts say the issue is an existential one for Jordan in particular. Half of Jordan's population of 11 million is of Palestinian origin, and since the establishment of Israel in 1948, many Palestinians have sought refuge there. In 1970 in what became known as "Black September," clashes erupted between the Jordanian army and Palestinian groups led by the Palestinian Liberation Organization (PLO).

AP Reporter Barred From Trump-Musk Event Over "Gulf Of America" Flap

World. The White House barred an Associated Press reporter from covering an event with President Donald Trump and adviser Elon Musk on Tuesday, in what the longtime newswire said was punishment for its style guide not adopting the president's new "Gulf of America" label. "It is alarming that the Trump administration would punish AP for its independent journalism," the AP said in a statement. "Limiting our access to the Oval Office based on the content of AP's speech not only severely impedes the public's access to independent news, it plainly violates the First Amendment." The Associated Press is a permanent member of the so-called "pool" that provides round-the-clock coverage of the president. As a newswire, stories written by AP reporters are published in newspapers and on websites across the US and world. The AP's style guide is also the basis for many broadcasting and news services, including Bloomberg News. In a Jan. 23 guidance note, the agency said that the "Gulf of Mexico has carried that name for more than 400 years" and that the organization would "refer to it by its original name while acknowledging the new name Trump has chosen." The White House Correspondents Association, which represents hundreds of journalists covering the presidency,



issued a statement calling on the White House to "immediately change course." "The White House cannot dictate how news organizations report the news, nor should it penalize working journalists because it is unhappy with their editors' decisions," WHCA President Eugene Daniels said. "The move by the administration to bar a reporter from The Associated Press from an official event open to news coverage today is unacceptable." During the presidential campaign, Trump repeatedly barred media outlets from his events over their coverage. During his first term, Trump officials sought to strip press passes from reporters but relented after a federal court sided with members of the media.



pollution in Dhaka, Bangladesh's capital. And seasonal forest fires cause problems in Brazil and North America. What health problems can air pollution cause? Air pollution is the second-largest risk factor for early death globally, behind high blood pressure, according to a recent report by the Health Effects Institute. Short-term exposure can trigger asthma attacks and increase the risk of heart attacks and stroke, especially in the elderly or people with medical problems. Long-term exposure can cause serious heart and lung problems that can lead to death, including

heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and lung infections. A recent analysis by the U.N. children's agency found that more than 500 million children in East Asia and Pacific countries breathe unhealthy air and the pollution is linked to the deaths of 100 children under 5 every day. June Kunugi, UNICEF Regional Director for East Asia, said the polluted air compromises growth, harms lungs and impacts their cognitive abilities. “Every breath matters, but for too many children every breath can bring harm,” she said. What’s the best way to tell if air is safe? Over 6,000 cities in 117 countries now monitor air quality, and many weather mobile apps include air quality information. But trying to gauge how bad the air is by looking at these numbers can be confusing. To help people understand air quality levels more easily, many countries have adopted an air quality index or AQI — a numerical scale where larger numbers mean worse air. They are also often assigned different colors to show whether the air is clean or not.

NEWS BOX

IND vs ENG, 3rd ODI: India's final chance to fine-tune side before Champions Trophy

India returns to the hallowed halls of the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad for the third and final ODI match of the series against England. This is the first time that the Indian team will play at the venue since their ODI World Cup final loss against Australia on November 19, 2023.

India will need to fine-tune their side before the Champions Trophy, at the same venue where a billion dreams came crashing down some time ago. A lot has happened since India's win in the Cuttack ODI as they were dealt a major blow in the form of Jasprit Bumrah being ruled out of the upcoming ICC event. A shuffle in the Champions Trophy squad was expected, and we got that as Harshit Rana was called up to replace Bumrah, while Varun Chakravarthy came in for Yashasvi Jaiswal.

Jaiswal, Shivam Dube and Mohammed Siraj were named as the non-travelling reserves for the tournament, which will start in a week's time.

India's Playing XI Issues

There are multiple issues that the Indian team is dealing with right now, and the majority of them are their own doing. Is Shreyas Iyer part



of the main playing XI? Is KL Rahul's best batting position No. 6? Was it right to fast-track Varun Chakravarthy and Harshit Rana for the ICC Champions Trophy? All of these questions need to be answered in the final ODI of the series.

And not only just that, there will be an onus on Gautam Gambhir to provide a clear picture on Rishabh Pant and Washington Sundar, who have not played a single match in the series. The Indian head coach would also need to take a call on Kuldeep Yadav, who was benched after the first ODI match of the series. India was concerned with the form of two of their most senior players in the format. One of them - the captain Rohit Sharma - has been able to silence his critics in the 2nd ODI match at the Barabati Stadium in Cuttack with an impressive hundred. Focus will be on Virat Kohli, who would hope to play a timely knock to return to form, just like Rohit did in the 2nd ODI. Kohli has played just one match in the series, where he got out to Adil Rashid - poking outside the off-stump. Conditions might be slower in Ahmedabad, which could prove to be a little difficult for him.

Champions Trophy 2025: Mitchell Starc pulls out, Steve Smith to lead Australia

New Delhi. Mitchell Starc has decided to skip the upcoming ICC Champions Trophy 2025 as Australia finalised their squad for the event on Wednesday, February 12. Steve Smith will be leading the team in Pakistan as the squad will miss the presence of the 'big 3' pacers with Starc's withdrawal.

Starc has decided to withdraw from the tournament for personal reasons, and will join Pat Cummins and Josh Hazlewood on the sidelines. Cummins and Hazlewood decided to sit out of the Champions Trophy due to injury concerns, while Australia will also be without the services of Mitchell Marsh. Marcus Stoinis will also be absent from the squad as he announced his shock ODI retirement ahead of the tournament. It has been revealed that Starc will not be commenting on why he decided to skip the Champions Trophy as he asked for privacy.

Cricket Australia has expressed their full support for the 35-year-old, who played a vital role in their ODI World Cup triumph in 2023. "We understand and respect Mitch's decision," chair of the national selection panel George Bailey said today. "Mitch is



deeply respected for his commitment to international cricket and the priority he places on performing for Australia."

"His well-documented ability to play through pain and adversity, as well as forgoing opportunities in other parts of his career to put his country first should be applauded."

"His loss is of course a blow for the Champion's Trophy campaign but does provide an opportunity for someone else to make a mark on the tournament." Starc appeared to be in some discomfort during the second Test against Sri Lanka and it is understood that he returned to Australia right after the match. This means that the pacer will also miss the 2-match ODI series against Sri Lanka, which begins in Colombo on February 12. The loss of the 'big 3' pace trio has opened the doors for Spencer Johnson, Ben Dwarshius.

Champions Trophy squad analysis: A smart Bumrah call and a baffling fondness for spin

☛ A smart decision and quite a few baffling calls contribute to the story of India's team selection for Champions Trophy 2025. Five of their 15 players are spinners while a young Yashasvi Jaiswal was left out after a failed experiment in the ongoing ODI series against England.

New Delhi. First things first. The Ajit Agarkar-led selection committee, coach Gautam Gambhir, and captain Rohit Sharma should be lauded for not taking a risk with Jasprit Bumrah. The narrative around team selection in the lead-up to the deadline for finalising the squad was that

Bumrah's absence would weaken the bowling attack and reduce its potency by nearly 50 percent. Pundits, fans, and former cricketers were vocal about the need for Bumrah to be in the UAE to shoulder the burden of the bowling attack. However, it seems the team management did not listen to the outside noise, and rightly so. Despite scans reportedly revealing no fresh injury concerns for Jasprit Bumrah, he was not included in the 15-man squad, which was finalised by the Indian cricket board (BCCI) with a typically near-midnight press communication on Tuesday, 11 February.

Top teams shouldn't be desperate; they should be mindful of the long-term impact of decisions made with short-term goals in mind. Rushing Bumrah's recovery from a back injury was probably not a risk worth taking for the Champions Trophy. Take Australia, for example: the world champions will be without their captain, Pat Cummins, as well as the other two members of their famed trio-Mitchell Starc and Josh

Hazlewood. The Steve Smith-led side will have a new-look bowling attack for the eight-team tournament, starting 19 February. This demonstrates the confidence they have in their resources. India's Champions Trophy



squad India, too, are trusting the likes of Mohammed Shami, despite his shaky form on return from a lengthy injury layoff, and Arshdeep Singh to lead the bowling attack in the UAE.

And with that, we come to the end of the discussion on thoughtful decisions in the team selection for the Champions Trophy.

Don't bench Kuldeep Yadav for Varun Chakravarthy in Champions Trophy: Aakash Chopra

New Delhi. Aakash Chopra has urged the Indian team management to not bench Kuldeep Yadav for Varun Chakravarthy during the Champions Trophy 2025. Varun was added to the squad for the tournament in place of Yashasvi Jaiswal as India finalised their squad on Tuesday, February 11.

Varun's addition meant that India will now carry 5 spinners for the Champions Trophy as they will play all their matches in Dubai. The Tamil Nadu spinner had replaced Kuldeep in the second ODI in Cuttack. After the announcement was made, Chopra took to X and said that the decision to go with 5 spinners would have worked in a venue like Sharjah and raised doubts about whether it was the way to go in Dubai. Chopra also urged India to play Varun and Kuldeep together if necessary. The former cricketer ended his tweet by



saying Kuldeep has to be India's premier spinner at the event.

"India has picked 5 spinners for Champions

Trophy. FIVE. Sharjah would be an ideal venue for this squad. Spin To Win. Dubai?? Not so sure. That surface hasn't helped spinners as much...ever. Also, I really hope that Kuldeep isn't benched for Varun. Play both if you must...but Kuldeep has to be India's premier spinner," said Chopra. Kuldeep Yadav's record in recent ICC events

In the last 2 ICC events, Kuldeep Yadav played a key role in India's success. During the ODI World Cup 2023, Kuldeep picked up 15 wickets in 11 matches and was India's 4th highest wicket-taker in the tournament as India reached the final.

The wrist spinner upped his game during the T20 World Cup 2024 as he picked up 10 wickets in 5 matches and was once again, the 4th highest wicket-taker for his side.

Manchester City boss Guardiola struggles to explain late collapse vs Real Madrid

New Delhi. Manchester City boss Pep Guardiola was lost for words as he struggled to explain how his side had another late collapse this season in the form of their 2-3 loss to Real Madrid in the Champions League Round of 16 qualifier on Tuesday, February 11. City were seemingly in cruise control by the 80th minute as an Erling Haaland brace had them in the lead at the Etihad stadium.

However, former City player Brahim Diaz' goal and Jude Bellingham's stoppage time winner ensured Los Blancos stole the win in the end. This is not the first time this season that City have allowed a lead slip at home. City let a 3-0 lead slip against Feyenoord in the Champions League, while Manchester United were able to get a win in the derby during stoppage time. Speaking to the reporters, as quoted by Reuters, Guardiola said that his side couldn't keep the result in the end.

UEFA Champions League: Full coverage

We arrived at the last minute with a result and we could not keep it," Guardiola told a press



conference. "After 2-1, many games it has happened, against Feyenoord in the Champions League (City led 3-0 in the 74th minute but were held to a 3-3 draw), against Brentford in the Premier League, against Manchester United, many games at the end

we give away," he added. Unfortunately it has happened so many times, it's difficult. "Blame belongs to all of us"

Guardiola went on to claim that the blame for the loss belongs to everyone and not just the players. The City boss admitted that his side

Manchester City boss Pep Guardiola struggled to find words to explain his side's late collapse against Real Madrid in the Round Of 16 qualifier of the UEFA Champions League on February 11. City let a 2-1 lead slip to lose the match 2-3 and hand the advantage to Madrid.

isn't stable enough during crucial moments at this time. "Belongs to all of us, not just the players."

"I don't have a problem to accept. To blame one specific player, that is ridiculous. It's all of us, me first. And of course, the players as well," he said. "They want it, how they run, how they do it, but the truth is we are not stable enough in that (crucial) moment."

City will now travel to Madrid on February 19 hoping to keep themselves alive in the tournament.



Under International Cricket Council protocols, a fair delivery means the bowler's elbow must not straighten from the shoulder level until the ball is released. Scientific research confirms some elbow extension is natural, but an action is illegal if it exceeds 15 degrees. Cricket Australia has come to Kuhnemann's defence, emphasising that this is the first time he has been reported in his eight-year career at the highest level. "The Australian team was notified of the match officials' referral following the second Test against Sri Lanka in Galle and will support Matt through the process of clearing this matter," Cricket Australia said on Wednesday. "Matt has played 124 professional matches since his debut in 2017, including five Test matches and four one-day internationals. He has played 55 Big Bash League games since 2018. "This is the first time in those eight years of professional cricket that his action been questioned. Cricket Australia will liaise closely with the ICC and independent experts in line with ICC regulations," it added. Australia is unlikely to be overly concerned and will hope Kuhnemann clears the assessment.

Afghanistan's Allah Ghazanfar set to miss Champions Trophy 2025 and IPL due to injury

Afghanistan suffered a big blow ahead of the Champions Trophy 2025 as the young spinner was ruled out of the tournament due to an injury. Ghazanfar will miss the IPL 2025 season due to the injury.

New Delhi. Afghanistan's young spin sensation Allah Ghazanfar will miss the upcoming Champions Trophy 2025 and IPL this year after suffering an injury. The Afghanistan Cricket Board made the announcement on Wednesday, February 12 that Ghazanfar sustained a fracture in the L4 vertebra during the recent tour of Zimbabwe. Ghazanfar was all set to play his maiden ICC event for the national team after making an incredible start to his ODI career.



In the 11 ODIs he has played so far, the 18-year-old has picked up 21 wickets at an average of 13.57. Ghazanfar has been replaced by Nangyala Kharoti in the main squad for Afghanistan. Additionally, ACB also announced that Mujeeb Ur Rahman would continue to miss playing in ODIs,

until has fully recovered.

"Afghanistan's young spin-bowling sensation, AM Ghazanfar, has been ruled out of the ICC Champions Trophy due to a fracture in the L4 vertebra, specifically in the left pars interarticularis. He sustained the injury during Afghanistan's recently held tour

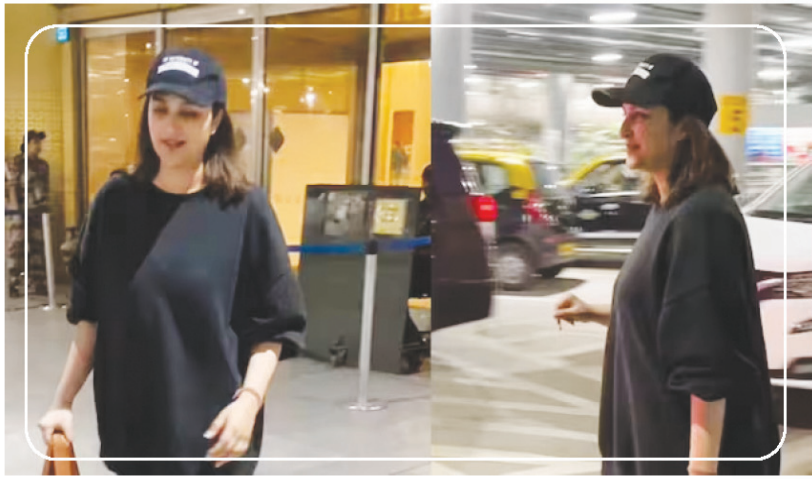
Zimbabwe, and will be sidelined for a minimum of four months and will remain under treatment during this period. Nangyal Kharoti, who was part of the reserves pool, has been promoted to the main squad for the Champions Trophy. Additionally, Mujeeb Ur Rahman's continues to miss the ODI action, until he has fully recovered," read the statement from ACB. Ghazanfar injury is also a huge blow for the Mumbai Indians as they had acquired the youngster for 4.8 crore rupees during the IPL 2025 auction. Afghanistan will begin their Champions Trophy campaign on February 21

Afghanistan squad for Champions Trophy 2025 Hashmatullah Shahidi (c), Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Sediqullah Atal, Rahmat Shah, Ikram Alikhil, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Nangyal Kharoti, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Farid Malik, Naveed Zadran.



Parineeti Chopra

Makes A Statement With Her Laid-Back Airport Look



Parineeti Chopra made a stylish touchdown in Mumbai on Tuesday morning. Just days back, the actress had headed home to Delhi right to celebrate her cousin Siddharth Chopra's wedding, who tied the knot with his ladylove Neelam Upadhyaya in an intimate yet lavish ceremony. Now, back in the city once again, the actress caught eyeballs with her bubbly personality, proving why she is a paparazzi favourite.

In a video shared on Instagram, the 36-year-old actress was spotted effortlessly strutting out of the airport terminal amid a flurry of camera flashes. Rocking an all-black outfit featuring an oversized tee and comfy shorts, Parineeti surely nailed the casual yet chic look. She paired her simple outfit with a baseball cap and white sneakers, proving that airport fashion can be simple yet statement-worthy.

As the clip played, the Amar Singh Chamkila actress could be seen pausing along her way to exchange a few words with the paparazzi while flashing her radiant smile. She even stopped briefly for the paps to click her pictures before she hopped into her car.

In other news, Parineeti created a lot of buzz in the media when she skipped attending Priyanka Chopra's brother's pre-wedding festivities. Her initial absence raised many eyebrows. However, she shut the murmurs when she arrived in Mumbai with her husband, Raghav Chadha, to celebrate the 'SidNee' wedding.

For the ceremony, the Ishaqzaade actress opted for an intricately embroidered crop blazer paired up with a printed lehenga and a silk bustier. The lehenga set is from Gazal Gupta's brand. She opted for a statement neckpiece and bangles to add an oomph factor to her overall look. Parineeti dropped a series of pictures on her Instagram, delighting her fans by giving a closer look at her modern, regal outfit. In the caption, she wrote, "A blazer and lehenga? YES!"

Speaking of her work front, the 36-year-old actress is busy filming her next project after the success of Imtiaz Ali-directed Amar Singh Chamkila, in which Diljit Dosanjh played the titular character. Parineeti portrayed his wife and singing partner, Amarjot Kaur. The biography, released on Netflix, immediately became a hit among viewers. As for her new film, the actress has not divulged many details about it except sharing about shoot locations, timings and a bunch of her co-stars.



Vidhu Vinod Chopra Kept Bobby Deol's Kareeb Co-Star Shabana 'Hidden': 'He Wanted The World To See Her Only..'



Vidhu Vinod Chopra's reputation as a perfectionist on set is well known, and filmmaker Siddharth P Malhotra recently shared some fascinating insights into his working style during Kareeb. The film starred Bobby Deol, who was still finding his footing in Bollywood, alongside Shabana (introduced as Neha). Years later, Shabana stepped away from films and tied the knot with actor Manoj Bajpayee. Siddharth recalled that VVC was so particular about Shabana's debut that he insisted she stay hidden from the public eye until the big reveal. "Vinod sir had kept me in-charge of Shabana. She was supposed to be kept in an apartment somewhere in Bandra. He wanted the world to see her only the day he brings her out," he revealed in a chat with Siddharth Kannan.

Years later, in a 2008 interview with Rediff, Shabana opened up about being forced to change her name and how she never actually wanted to act. "But they saw me on television and coaxed me to do the film. They chased me. I was not interested and refused. They spoke to my parents and got their approval," she shared.

Siddharth also recalled a nerve-wracking moment on set when a water snake made an unexpected appearance during the filming of Chori Chori. Bobby, submerged in water for the shot, spotted the snake and immediately called out to the director. But VVC, determined to capture the perfect lighting, refused to cut the shot. "There was a water snake close to Bobby and he kept saying 'Vinod, there's a snake here,'" Siddharth recounted. Once the take was complete, Bobby bolted in the opposite direction.

Reflecting on the experience in the same Filmfare interview, Bobby admitted that while Shabana had a "tough time" with VVC constantly yelling at her, he himself was treated differently. "No one pulled me up, maybe because my father's famous," he had said.

Harshvardhan Rane Celebrates Sanam Teri Kasam's Successful Re-run In Theatres



Harshvardhan Rane is overjoyed as his Bollywood debut Sanam Teri Kasam is finally getting the recognition it deserves with its re-release. Originally released in 2016, the film struggled at the box office, collecting only Rs 9.11 crore despite receiving positive reviews. However, the re-release is proving to be a success, earning an impressive Rs 3-3.25 crore on Day 4 and bringing its total revenue to Rs 22.09 crore, as per the makers. Amid the film's renewed success, Harshvardhan was recently spotted in the city, channelling his character Inder from Sanam Teri Kasam.

In a video shared by Viral Bhayani on Instagram, the actor is seen posing for the paparazzi in a grey shirt paired with brown cargo pants—the same outfit he wore in the film. As the clip progresses, the Haseen Dillruba actor is seen engaging with the paps, further delighting his fans.

Not just this, the actor also recently surprised his fans watching Sanam Teri Kasam in the theatres. During his appearance, Harsh wore the same black suit that his character Inder wore in the film's climax scene.

Sharing a video of the same on Instagram, the actor wrote in the caption, "I went below the producer's office to request for re-release, now next step I will do an 11 day (water only) fast below his office to request him for Part 2. 9 years ago, the Producer gave it their blood, Director gave it their sweat, Mawra gave it her soul, and now you gave it your tears!! I will give my life for part 2, Tumhaari Kasam."

Helmed by Radhika Rao and Vinay Sapru, the film also featured Pakistani actress Mawra Hocane, Manish Chaudhary, Murali Sharma and Sudesh Berry in pivotal roles. Recently in an interview with India Forums, filmmakers Radhika Rao and Vinay Sapru disclosed that the sequel is already in the works, and they have a clear idea of where Inder's (Harshvardhan Rane) journey will take him next. Moreover, the makers are planning to release Sanam Teri Kasam 2 on the occasion of Valentine's Day 2026. Keywords: Harshvardhan Rane Sanam Teri Kasam, Harshvardhan Rane spotted in the city, Harshvardhan Rane Instagram.

Urvashi Rautela

Reacts To Backlash Over Dabidi Dibidi Dance Moves: 'During Rehearsals...'

Urvashi Rautela and Nandamuri Balakrishna's dance moves in the song 'Dabidi Dibidi' from their recently released film 'Daaku Maharaaj' faced massive backlash on social media. Netizens slammed the choreography by Shekhar Master, calling the moves 'crass' and 'vulgar'. Urvashi has now addressed the criticism over the dance moves, saying that the team absolutely didn't anticipate this kind of a reaction. She said that they thought it would be taken positively, and that they didn't expect people to talk about the song in this manner. While speaking with The Hollywood Reporter India, Urvashi Rautela said that the song Dabidi Dibidi is made for Nandamuri Balakrishna's fans, and that every lyric is crafted according to their mindset. "When you look at my rehearsal clips, everything went really well. It was like how we usually choreograph for any song. I was working with Master Shekar, with whom I've collaborated before this was my fourth time. So it wasn't like I was shocked or doing something completely out of the ordinary. During rehearsals, everything was smooth and under control. But honestly, everything happened so suddenly that it's been hard to assess why people are talking about the choreography in this way. We didn't realise it would be received like this because, during rehearsals, everything went as planned," said Urvashi. She further added that the way the song was received was surprising for her. She said that it is a peppy, massy song, and that they never anticipated the backlash. "We never expected people to talk about it in this manner. As a team, we truly didn't anticipate this reaction," she said. Urvashi thought that it would be taken positively. However, she said that she has always kept her identity and professionalism separate. She said that while she embraces constructive criticism, she doesn't let it overshadow her passion for her work. The music video of the song Dabidi Dibidi, composed by S Thaman, shows Urvashi Rautela dressed in a crop top and skirt, while Nandamuri Balakrishna is seen hitting her belly button on beats, and pulling her up by her dress. Later in the song, the 64-year-old actor is seen hitting the actress on the rear. Clips from the music video went viral on social media last month, as netizens called out the 'cringe' and 'vulgar' moves.

